● वर्ष-3
● अंक-293
रायपुर, गुरुवार
18 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ये 5 वॉटर कोर्स दिलाएंगे विदेश जाने..

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से रेल परियोजनाओं पर की चर्चा

जल्द शुरू होंगीं छत्तीसगढ़ की चार प्रमुख रेल परियोजनाएं, रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 जुलाई को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने इस दौरान राज्य की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना और रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को जल्द शुरू करने का आग्रह किया।

धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना (240 किमी)- मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्थलगाँव, कुनकुरी, जशपुर नगर, गुमला आदि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ेगी। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक (कोरबा) क्षेत्र को लोहरदगा से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची के होकर मध्य भारत से जोड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है।

अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना (200 किमी)- इस परियोजना की मांग आजादी से पहले 1925 में की गई थी। हालांकि, 1948 में मंजूरी

मिलने के बावजूद यह परियोजना अब तक अधूरी रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना अंबिकापुर (उत्तरी छत्तीसगढ़) को बरवाडीह (झारखंड) से जोड़ेगी और परसा, राजपुर, चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9000 करोड़ रुपए है।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई लाइन परियोजना (277 किमी)- मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना देश के पश्चिमी क्षेत्र में एसईसीएल और एमसीएल कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बायपास करते हुए बलौदाबाजार क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए है।

रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना (140 किमी)- रेलवे पहले से ही दल्ली-राजहरा-रावघाट 95 किमी नई रेलवे लाइन का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने सुझाव दिया कि इस लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक लौह अयस्क की निकासी के कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की संभावनाओं और लाभों को स्वीकार किया और इन पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और रेलवे मंत्रालय इन्हें प्राथमिकता देगा।

विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर गृहमंत्री शाह से चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन ञ2047 पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य सरकार ने आठ अलग-अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से आम लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा कर एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह को राज्य में माओवादियों के सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ की जा रही प्रभावी कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने नक्सल ऑपरेशन और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में भी गृहमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि माओवादी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है.

मोदी को सिर्फ घमंड की परवाह, मिशन इंद्रधनुष के तहत नहीं हो रहा बच्चों का टीकाकरण : खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण करने में कथित विफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, पीएम केवल घमंड की परवाह करते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इसे मुख्य पाप करार देते हुए दावा किया कि 2023 में 16 लाख बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीटीपी) और खसरे के टीके नहीं दिए गए थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीओवीआईडी महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए लगभग आधे आवेदन पीएम केयर्स फंड द्वारा बिना कोई कारण बताए, खारिज कर दिए गए। मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान है। 2014 में शुरू की गई योजना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नियमित टीकाकरण सेवाएं उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचें जो पहले टीकाकरण से चूक गए थे या टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर हो गए थे। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई टीकाकरण में भारत की मजबूत नींव को बर्बाद कर रही है। मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान है। 2014 में शुरू की गई योजना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नियमित टीकाकरण सेवाएं उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचें जो पहले टीकाकरण से चूक गए थे या टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर हो गए थे। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लाखों बच्चों का टीकाकरण न करके बहुत बड़ा पाप किया है। टीकाकरण की उपेक्षा का अर्थ है बहुमूल्य जीवन की हानि। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा टीकाकरण में भारत की मजबूत नींव का लाभ मोदी सरकार द्वारा बेशर्मी से बर्बाद कर दिया गया

भाजपा ने अजित से 'महायुति' से बाहर निकलने के लिये कहा

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मराठी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि इसके जरिये भाजपा उप मुख्यमंत्री अजित पवार नीत राकांपा को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ 'महायुति' से अलग होने का संदेश दे रही है। साप्ताहिक विवेक में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन भावना तेजी से उभरी है, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खराब प्रदर्शन किया। राकांपा के प्रवक्ता क्लाईड क्रास्टो ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको एहसास हो गया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।

उन्होंने कहा, ''सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पैमाने पर राकांपा (एसपी) के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा भी इस पूरे मामले में सावधानी से काम कर रही है क्योंकि वह चुनाव जीतना चाहती है।''

क्रास्टो ने दावा किया, ''लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ गठबंधन उन्हें लोकसभा चुनावों की तरह अगले चुनाव में भी हराएगा ... साप्ताहिक (विवेक) में छपा लेख उन तरीकों में से एक है जिनसे वे खुद को अजित पवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी न किसी तरह से उन्हें (महायुति) छोड़ने के लिए कह रहे हैं।'' राकांपा(एसपी) प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस से जुड़े प्रकाशन ने कुछ सप्ताह पहले भी इसी तरह की सामग्री के साथ एक अन्य लेख लिखा था।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 हार्डकोर नक्सली ढेर, दो जवान घायल

कांकेर। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर आज सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच 5 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। वहीं दो जवानों को गोली लगी है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर गढचिरौली मुख्यालय लाया गया है। पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है और सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में डीवीसी लेवल के हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शवों के साथ-साथ बेहद घातक हथियार सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है। मारे गए नक्सलियों पर महाराष्ट्र शासन की ओर से 51 लाख का इनाम घोषित था। वहीं घायल जवानों को छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से एंबुलेंस के माध्यम से बांदे लाया गया. जहां से हेलीकाप्टर से उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया.

प्रमुख समाचार

सुकमा में लगातार बारिश से 24 गांवों का संपर्क टूटा

सुकमा। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच अंदरूनी इलाकों में जनजीवन पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां नदी नाले जल भराव के चलते उफान पर चल रहे हैं। इस बीच सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा में मल्लेबाग तेज पुल बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके चलते जगरगुंडा से सुकमा जिला मुख्यालय के लिए अब वाहनों की आवाजाही भी कई घंटे से प्रभावित रही। इन इलाकों में दो दशकों से पुल का काम नहीं हुआ था। हाल में इन इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम भी जारी है और बारिश के बीच पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से इन इलाकों के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल, प्रशासन ने इस क्षतिग्रस्त पुल से लोगों को सुरक्षा के लिहाज से आवाजाही न करने की अपील की गई है। क्योंकि सुकमा जिले के लिए जगरगुंडा समेत दो दर्जन से ज्यादा गांव का एकमात्र रास्ता यहीं से गुजरते हैं।हालांकि जगरगुंडा दंतेवाड़ा क्षेत्र का सीमावर्ती इलाका है, जो फिलहाल सड़क से जुड़ा है। लेकिन इन ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा होकर भी गुजरना पड़ सकता है।

पेपर लीक मामला: नीतीश और भाजपा की मिलीभगत

नई दिल्ली। पेपर लीक, कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बिहार सुर्खियों में है। विपक्ष नीतीश सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन सब के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि बिहार में नैतिक तौर पर टूटे निजाम का शासन है। सरकार की हर शाख पर एक-एक नक्कारा लाचार बैठा है। उन्होंने आगे लिखा कि अवसरवादिता के पुरोधा आत्ममुग्ध नीतीश कुमार व भाजपा की मिलीभगत वाली फेल डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती में बिहार बेपटरी हो चुका है। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली रोहिणी आचार्य ने कहा कि मूलभूत व्यवस्थाएं बदहाल हैं, अफसरशाही सरकार चलाने वालों व विधायिका पर हावी है, संरचनाओं को भ्रष्टाचार का दीमक चाट कर खोखला कर रहा है, कानून- व्यवस्था अपराधियों के रहम-ओ-करम (अनुकंपा) पर है, सतत व् समग्र विकास के मानकों पर खुद को साबित करने में सरकार विफल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की धाँधली का हब बनाये जा चुके बिहार में युवाओं का भविष्य गर्त में धकेलने को सत्ताधारी गठबंधन आमादा है.

डोडा आतंकी हमला: एक साल में मारे गए 55 जवान

जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि डोडा की घटना पहली नहीं बल्कि पिछले साल जम्मू पर हमले की कई घटनाओं में से एक है। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि पर कथित निष्क्रियता को लेकर केंद्र से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब आप डोडा के बारे में पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पहली बार हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले साल जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पर लगातार हमले हुए हैं। अब्दुल्ला ने सरकार और पुलिस बलों से स्थिति की जिम्मेदारी लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग 55 सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में हम यह पूछने पर मजबूर हैं कि सरकार क्या कर रही है। वे कहते हैं कि उग्रवाद ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा होता नहीं दिखता। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरआर स्वैन ने मंगलवार को अपनी राय व्यक्त करते हुए आरोप लगाया था कि समाज में पाकिस्तान की सफल घुसपैठ के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्षेत्र में मुख्यधारा की पार्टियों पर अपने चुनावी लाभ के लिए आतंकी नेटवर्क विकसित करने का भी आरोप लगाया।

कर्नाटक कोटा विवाद के बीच आईटी कंपनियों को ऑफर

नई दिल्ली। कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के कदम पर विवाद और नैसकॉम द्वारा फैसले पर चिंता जताए जाने के बीच, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश ने आईटी कंपनियों का आंध्र प्रदेश के विजाग में व्यवसाय स्थानांतरित करने का स्वागत किया। टीडीपी विधायक ने तुरंत कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से बिना किसी प्रतिबंध के आपके आईटी उद्यम के लिए सबसे उपयुक्त कुशल प्रतिभा के साथ तैयार है। नैसकॉम सदस्य को एक्स पोस्ट के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विजाग में हमारे आईटी, आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने व्यवसायों का विस्तार करने या स्थानांतरित करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सरकार की ओर से बिना किसी प्रतिबंध के आपके आईटी उद्यम के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की सुविधाएं, निर्बाध बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे उपयुक्त कुशल प्रतिभा प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश आपके स्वागत के लिए तैयार है। कृपया सम्पर्क करें!

माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में लगभग ?50 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली, जो मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की थी, जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के पैसे से खरीदा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक ने अपराध से जुड़ी गतिविधियों के पैसे से 2.377 हेक्टेयर जमीन हासिल की और उसे हुबलाल नाम के राजमिस्त्री के नाम दर्ज करा दिया। अतीक ने यह भी दावा किया कि जरूरत पड़ने पर वह जमीन अपने नाम कर लेगा। नवंबर 2023 में पुलिस ने इस जमीन को जब्त कर लिया। अग्रहरि ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त कर ली और जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया। हालाँकि, स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने मामले को प्रयागराज की गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्रवाई को निष्पक्ष और उचित माना, और संपत्ति आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।

कहां गया रेल बजट

92 साल की परंपरा खत्म कर रेल बजट और आम बजट एक साथ क्यों पेश किया जाने लगा?

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश कर 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किया। पहले संसद में दो बजट पेश किए जाते थे एक %रेल बजट% और दूसरा %आम बजट%। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्होंने 1 फरवरी, 2017 को आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया।

इस बार भी रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी, इस में रेल बजट भी शामिल होगा। हालांकि, हमेशा ऐसा नहीं था। वित्त वर्ष 2016-17 तक केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था। 92 साल पुरानी यह प्रथा तब समाप्त हुई जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया।

1924 में शुरू की गई थी रेलवे के लिए अलग बजट की परंपरा

रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। यह फैसला एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था, पर 2017 से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एक्वर्थ रेलवे को एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में लाए थे। इसके बाद उन्होंने 1924 में इसे आम बजट से अलग पेश करने का फैसला किया तब से लेकर साल 2016 तक यह अलग-अलग पेश किया जाता रहा। भारत को आजादी मिलने के बाद पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो आम बजट भी पेश किए थे। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था।

क्यों समाप्त की गई रेल बजट अलग से पेश करने की परम्परा?

नवंबर 2016 में, रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर देगी। यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य

बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों और देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा रेल बजट के साथ वितरण पर एक अलग पत्र पर आधारित था। इसके अनुसार यह तय किया गया कि वित्त मंत्रालय रेलवे के अनुमानों के साथ एक विनियोग विधेयक तैयार करेगा और संसद में प्रस्तुत करेगा। वित्त मंत्रालय इससे जुड़े सभी विधायी कार्य भी संभालेगा। भारतीय रेलवे को सरकार को लाभांश का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही रेलवे का पूंजी प्रवाह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर रेल मंत्रालय को अपने पूंजीगत व्यय के हिस्से को कवर करने के लिए वित्त मंत्रालय से सकल बजटीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि भारतीय रेलवे अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से बाजार से संसाधन जुटाना जारी रखेगी।

वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भी रेलवे से होने वाली राजस्व की प्राप्ति आम राजस्व प्राप्तियों से 6 प्रतिशत अधिक थी। तब सर गोपालस्वामी आयंगर समिति ने यह सिफारिश दी थी कि अलग रेलवे बजट की यह परम्परा जारी रहनी चाहिए। इस आशय के संबंध में 21 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। गौरतलब है कि इस अनुमोदन के अनुसार 1950-51 से लेकर अगले पांच साल तक की अवधि के लिये ही रेलवे बजट को अलग पेश किया जाना था। लेकिन यह परम्परा 2016 तक जारी रही।

देश की आजादी के बाद धीरे-धीरे रेलवे के राजस्व में कमी आने लगी और 70 के दशक में रेलवे बजट सम्पूर्ण राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत ही रह गया और 2015-16 में रेलवे का राजस्व कुल राजस्व का 11.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। उसके बाद विशषज्ञों ने अलग रेलवे बजट को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसके बाद सरकार ने रेल बजट और आम बजट का विलय कर दिया।

आम बजट में रेल बजट के विलय के क्या फायदे हैं?

रेल और आम बजट के विलय का उद्देश्य केंद्र सरकार के वित्तीय लक्ष्य को एक समग्र दृष्टिकोण देने के अलावे राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच परिवहन योजना में सुधार करना था। ऐसा करने से वित्त मंत्रालय को मध्य-वर्ष की समीक्षा के दौरान संसाधनों का आवंटन तय करने में अधिक लचीलापन हासिल हुआ।

शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था बदहाल, अनवरपुर में एक अध्यापक के जिम्मे 71 बच्चे

महासमुन्द। महासमुंद जिले में लगातार शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था बदहाल होते हुए नजर आ रही है। जुलाई माह में जैसे ही स्कूलों में रौनक लौटी, वैसे ही जिले के अलग-अलग स्कूलों से शिक्षकों की कमी ने शिक्षा व्यवस्था पर विभाग के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। ताजा मामला महासमुंद जिले की बागबाहरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला अनवरपुर से सामने आया है। जहां विगत 2 वर्षो से शिक्षको की कमी से स्कूल जूझ रहा है।

शासकीय प्राथमिक शाला अनवरपुर की दर्ज संख्या 71 है। पिछले वर्ष इस स्कूल की दर्ज संख्या 79 थी, लेकिन शिक्षको की कमी और घटते शिक्षा स्तर को देखते हुए पालकों ने अपने बच्चो को प्राथमिक शाला अनवरपुर से निकाल कर दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया है। ग्राम पंचायत अनवरपुर के जनप्रतिनिधि और पालक समिति के सदस्य लगातार शिक्षको की मांग के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को मांग कर चुके है। वही पिछले सत्र में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भी घेराव भी किया गया था। लेकिन इस स्कूल में अभी तक शिक्षको की कमी पूरा नहीं हो पाया है। इस स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे स्कूल के 71 बच्चों का भविष्य है।

इसके साथ ही इस एक शिक्षक को ही अपने स्कूली कार्य भी निपटाना होते हैं। जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने बच्चो के पढ़ाई के लिए गांव के ही एक शिक्षक को स्वयं के व्यय से पढ़ाने के लिए रखा है। लेकिन यह इस स्कूल की समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। गौरतलब हो की शिक्षकों की कमी से जूझते प्राथमिक स्कूल अनवरपुर के 2 होनहार बच्चो का चयन एकलव्य स्कूल के लिए भी हुआ है।

बच्चे का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। ग्रामीणों ने कहा है कि, 20 जुलाई तक शासकीय प्राथमिक शाला अनवरपुर में शिक्षको की कमी को पूरा नहीं किया जायेगा, तो सभी पालक अपने बच्चों का टीसी निकलवाकर अपने बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में करवा देंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 225 प्राथमिक शाला ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे है। वही 05 पूर्व माध्यमिक शाला और 04 हायर सेकेंडरी स्कूल भी एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। वहीं जिले के 11 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है। ऐसे में सरकारी स्कूलों का यह हाल, जिले में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करता है और शिक्षा विभाग के कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।

पंचायत भवन में लग रहा स्कूल, एक कमरे में पढ़ते हैं बच्चे

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिले में प्राइमरी स्कूल किस तरह से चल रहे हैं, इसकी बानगी ग्राम पंचायत संतोषीनगर में देखने को मिली है। यहां के ग्राम पंचायत संतोषीनगर के शासकीय प्राइमरी स्कूल पिछले दो सालों से पंचायत भवन के एक कमरें में संचालित हो रहा है। यहां स्कूल का अलग भवन नहीं होने के कारण बच्चे पंचायत भवन में ही बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं।

संतोषी नगर ग्राम पंचायत में बच्चे मुश्किल हालत में पढ़ाई करते हैं। सिर्फ एक कमरे में बच्चे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन होता है।उस दिन शिक्षक बच्चों को लेकर खुले मैदान में चले जाते हैं।जहां तपती धूप,बारिश और ठंड में बच्चों को पढ़ाई करनी होती है।स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की माने तो दो साल पहले पुराना स्कूल जर्जर होने के कारण डिसमेंटल कर दिया गया था। तब से बच्चों को सुरक्षित भवन नहीं मिल सका था।

शिक्षक राजकुमार ने कहा दो साल पूर्व पुराना स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण डिस्मेंटल कर दिया गया था। इसके बाद से सुरक्षित भवन नहीं मिल सका है। एक अतिरिक्त कक्ष तो बन रहा था। लेकिन वह भी अब तक आधा अधूरा है।

वहीं गांव के सरंपच के मुताबिक उन्होंने स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्ष बनवाया है।लेकिन शासन से पैसा नहीं मिलने के कारण वो पूरा नहीं हो सका है। इस मामले में बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला अभी आया है।यदि वहां भवन होगा तो बच्चे भवन में बैठेंगे।यदि जर्जर है तो उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ डीएन मिश्रा ने कहा मैं चेक करा लेता हूं अगर वहां भवन है तो बच्चे भवन में बैठेंगे। अगर जर्जर भवन है तो उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था बनाएंगे।

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में निर्माणाधीन दर्जनों स्कूल आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं कई स्कूल जर्जर हो चुके हैं। जिसको लेकर प्रशासन ने डिस्मेंटल की कार्रवाई तो की है। लेकिन अब तक उन स्कूलों की जगह में नया भवन बनवाना शायद भूल गई है। बहरहाल बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर पूरे साल एक ही भवन में संचालित होगी और बच्चों को स्कूल भवन का इंतजार करना पड़ेगा।

नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चलते थमेंगे यात्री ट्रेन के पहिए

28 जुलाई से एक सप्ताह तक चलेगा

जगदलपुर। नक्सलियों के द्वारा 28 जुलई से शहीदी सप्ताह मनाने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर रेलवे विभाग की ओर से अपनी तैयारी पूरी कर ले रहे है, जिससे कि नक्सलियों के द्वारा रेलवे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके।

बताया जा रहा है कि नक्सलियों के इस सप्ताह के शुरू होने के साथ ही केके लाइन पर यात्री ट्रेन के पहिये थम जायेगे, इस दौरान पूरे सप्ताह तक यह ट्रेन बैलाडीला तक नही भेजे जाएंगे, इसके अलावा दंतेवाड़ा में ही पैसेंजर ट्रेन के साथ ही नाइट एक्सप्रेस को भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि यही ट्रैन है जो विशाखापत्तनम से जगदलपुर और फिर दंतेवाड़ा और बैलाडीला तक जाता है, इस ट्रेन में ना सिर्फ बस्तर के लोग बल्कि ओड़िसा से भी काफी संख्या में यात्री रोजाना सफर करते है, एक सप्ताह तक इस ट्रेन के नही चलने से आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी ट्रैन के माध्यम से रोजाना 2 से 3 सौ लोग विशाखापत्तनम अपना इलाज कराने के लिए जाते है। ऐसे में इस ट्रेन के बंद हो जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिलहाल रेलवे ने अपने ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे है, जिससे कि नक्सलियों के द्वारा रेलवे को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचा सके।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों के विवाह की चिंता हुई दूर

रायगढ़ में 45 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

रायगढ़। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजुलखर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। गतदिवस को रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 45 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को कन्या के नाम से 35 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। उपहार के रूप में बैग, श्रृंगार सामाग्री, कपड़े इत्यादि वर-वधु को दिया गया तथा जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र दिया गया।

इनमें से गोपालपुर, बोईरदादर की निवासी श्रीमती देवंती सिदार ने और भगवानपुर निवासी श्रीमती भारती ने बताया कि उनकी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 16 जुलाई 2024 को हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनका पंजीयन किया गया और इस योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वे अभी अपने अपने पति के साथ बेहद खुश है। गरीबी के कारण परिवार वालों के लिए शादी कराना बहुत बड़ी चुनौती थी पर इस योजना के चलते यह चुनौती आसानी से हल हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवम् बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को धन्यवाद देते हुए हितग्राहियों कहा कि इस योजना ने हमारे माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर धूमधाम से विवाह करने समर्थ बना दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। महतारी वंदन योजना, महतारी जतन योजना, इनमें से और एक योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर, आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कर माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है, जिनके घर में बेटियां होती है, उनके माता-पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हजारों परिवारों के माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर उनकी चिंता दूर कर रही है।

बलौदाबाजार-भाटापारा में बदमाशों के निकले पंख, नहीं रहा पुलिस का खौफ

अब एसआई की कार को फूंका

बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदाबाजार हिंसा के बाद से ही जिले की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। पुलिस अब भी कलेक्टोरेट एसपी दफ्तर आगजनी मामले के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है।वहीं दूसरी तरफ टुटपुंजिए बदमाश और चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है।बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद है कि ना तो उन्हें कानून का खौफ है और ना ही सजा का डर।हालिया घटना में बदमाशों ने तो हद ही पार की है।इस बार बदमाशों के निशाने पर निपनिया थाना प्रभारी की गाड़ी आई।जिसे बीती रात किसी ने फूंक दिया।

ग्रामीण थाना क्षेत्र के निपनिया चौकी में प्रभारी किशुन कुम्भकार के घर के सामने खड़ी कार में किसी अज्ञात आरोपी ने आग लगा दी।जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग राख के ढेर में बदल चुकी थी।इस मामले में जहां एक तरफ पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।वहीं दूसरी तरफ आगजनी के बाद फायर ब्रिगेड टीम की लापरवाही भी देखने को मिली।थाना प्रभारी ने जब आग लगने की सूचना देने के लिए भाटापारा नगरपालिका के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कॉल किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। तब बलौदाबाजार की अमेरा स्थित फायर स्टेशन की टीम की मदद से आग बुझाई गई।

कार में आग लगने की घटना के बाद चौकी प्रभारी किशुन कुम्भकार से लगातार उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। घटना की भाटापारा ग्रामीण थाना प्रभारी अमित पाटले ने पुष्टि की।

थाना प्रभारी अमित पाटले ने कहा रात लगभग एक बजे की घटना है। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। घटना क्यों और कैसे हुई अभी पता नहीं चला है।

आपको बता दें कि बलौदाबाजार में बदमाशों के पंख निकल आए हैं।यहां कुछ ही दिन पहले आबकारी उपनिरीक्षक जलेश सिंह को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर बदमाश ने पीटा था।इस केस में पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर जुलूस निकाला।लेकिन वो जुलूस में अपनी बत्तीसी दिखाता नजर आ रहा था।शायद उसे पता था कि पुलिस किस तरह से खातिरदारी करेगी।इससे पहले एक महिला आरक्षक की स्कूटी उसी के घर के सामने से पार कर दी गई।जो अब तक लापता है।वहीं गार्डन के पास से बाइक को चोरों ने उड़ा लिया।अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जिले में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से होगी। वहीं इस मामले में नागरिकों का कहना है कि इसका मुख्य कारण नशे का अवैध कारोबार है। जिसकी युवा पीढ़ी आदि हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जलस्तर बढ़ने से बीजापुर गंगालूर मार्ग हुआ अवरूद्ध

बीजापुर। जिले में आधी रात हुई झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जगदलपुर से भोपालपटनम राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के जांगला के पास पानी भरने से मार्ग अवरूद्ध हो गया है। बारिश की वजह से चेरपाल नदी में जलस्तर बढने से नैमेड से कुटरू व बीजापुर-गंगालूर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। आधी रात को भारी बारिश होने से नदी-नाले उफान पर है। छोटे-बड़े वाहनों के अलावा बसों के पहिये भी थम गए हैं। भारी बारिश होने से किसानों का कार्य भी प्रभावित हुआ है। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। जांगला में सड़क पर पानी भरने से विधायक विक्रम मंडावी ने कमर से ऊपर तक बहते हुए पानी में स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सड़क पार किया। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम के भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जोखिम लेना पड़ा। विधायक ने बताया कि कुटरू मार्ग में भी बाढ़ जैसे हालात है। वहीं नेशनल हाईवे-63 पर भारी बारिश से आवागमन ठप होने से बसों के यात्रियों को परेशान का सामना करना पड़ रहा है।

पौधे लगाने के साथ ही उसकी देखभाल भी जरूरी : जांगड़े

जांजगीर-चांपा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस लाईन खोखरा में जिला प्रशासन एवं वन मंडल जांजगीर-चांपा द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े सहित क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी नागरिक, स्कूल कालेज के बच्चें, संगठन, हर नागरिक पौधे अवश्य लगाएं। पौधे लगाने साथ ही उसकी देखभाल जरूर करें। जांगड़े ने बेल का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक से अधिक नागरिकों को शामिल होने का आग्रह किया है। यह अभियान हमारे आने वाले कल के लिए एक सुखद अनुभूति होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान को घर - घर पहुंचाएं है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने जन्मदिन, शादी, वैवाहिक वर्षगांठ एवं अन्य खुशी के अवसर पर एक पेड़ लगाने की अपील की।

मालगाड़ी के सामने युवक ने लगाई छलांग, उपचार जारी

जगदलपुर। जगदलपुर में गीदम रोड़ रेलवे स्टेशन में बुधवार की दोपहर को एक युवक ने मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी। इस घटना में युवक का पैर कटकर अलग हो गया। घटना की जानकारी लगते ही आरपीएफ पुलिस के साथ ही 108 की टीम मौके पर पहुंच घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस ने बताया कि दोपहर को मालगाड़ी के ड्राइवर ने आरपीएफ को सूचना दिया कि एक युवक मालगाड़ी के सामने कूद गया है, सूचना पर पहुँची पुलिस ने युवक के पास से मिले फोन के आधार पर उसकी पहचान राजेश मिश्रा 37 वर्ष निवासी गीदम रोड़ के रूप में हुई है। पुलिस का मानना है कि युवक ने सुसाइट करने के इरादे से ही ट्रेन के सामने छलांग लगाई है, मौके पर जब पुलिस पहुँची तो युवक का पैर कटकर अलग हो गया था, साथ ही पटरी के उस पार गिरा पड़ा हुआ था, फिलहाल घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया है, साथ ही परिजनों को भी अस्पताल आने की बात कही गई है।

जलती आग में गिरा नाबालिग मोहर्रम के दौरान हुआ हादसा

कोरबा। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम नोनबिर्रा में भी मोहर्रम आयोजन किया गया जिसमें अंगार अलाव जलाकर उसके आसपास लोग मौजूद थे। 17 वर्षीय नाबालिग के गांव के अन्य लड़के भी मौजूद थे। इन्हीं में शामिल एक किशोर सरवन भी मौके पर था। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर लड़कों में तू-तू मैं-मैं हो गया और धक्का-मुक्की में सरवन जलते अंगार में गिर पड़ा। सरवन के अंगार में गिरते ही अफरा-तफरी मच गई और उसे तुरंत बाहर निकाला गया। सरवन का पीठ का कुछ हिस्सा झुलस गया है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही रात में डायल 112 की टीम और करतला पुलिस मौके पर पहुंची थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान ने बताया नोनबीर्रा गांव में तीन भाई एक साथ मोहर्रम कार्यक्रम देखने गए हुए थे इस दौरान अंगार के पास बैठे हुए थे कुछ नाबालिग 5 से 6 की संख्या में आए और उसे धक्का देकर भाग गए इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही शुरू कर दी है।

मामा के साथ घर से निकला भांजा हुआ लापता

कोरबा। सर्वमंगला रेलवे फाटक में मालगाड़ी के पार होने का इंतजार कर रहे मामा-भांजा एक दूसरे से बिछड़ गए। किसी तरह मामा तो अपने ससुराल पहुंच गया लेकिन भांजा पांच दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटा। उसकी बाइक रेलवे फाटक के समीप लावारिस हालत में खड़ी मिली। पड़ोसी जिले से परिजन कोरबा शहर युवक की तलाश में पहुंचे। उनकी मदद के लिए पुलिस ने भी हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। भारत नगेसिया नामक युवक ने बताया कि वे रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना अंतर्गत राजापुर के रहने वाले हैं। उसका कटघोरा के समीप ग्राम लखनपुर में ससुराल है। वह अपने मुंह बोला भांजा विष्णु प्रसाद (32) के साथ छह दिन पहले कोरबा आया हुआ था। वे दोपहर करीब 12 सर्वमंगला रेलवे फाटक के समीप पहुंचे। वह बंद फाटक को पार कर दूसरी तरफ चला गया जबकि विष्णु बाइक लेकर फाटक खुलने के इंतजार कर रहा था। मालगाड़ी के निकलने पर विष्णु गायब मिला। वह काफी देर तक भांजे को तलाशता रहा।

कोटा में डायरिया के बाद मलेरिया का प्रकोप, 4 लोगों में हुई पुष्टि

■ 1 युवक की हालत नाजुक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मलेरिया अब बेकाबू होता दिख रहा है।बीजापुर के पोटाकेबिन में मलेरिया के कारण दो छात्रों की मौत हुई है।वहीं 180 से भी ज्यादा छात्र मलेरिया की चपेट में हैं।वहीं अब प्रदेश की न्यायधानी में मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला है। जहां कोटा क्षेत्र में मलेरिया के चार मरीज मिले हैं।जिनमें से एक की हालत गंभीर है।जिन्हें सिम्स रेफर किया गया है। मलेरिया के पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग तेजी से लोगों की जांच कर रहा है।

मलेरिया केस के कारण अब स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के दर्जनों लोगों का मलेरिया टेस्ट किया है। आपको बता दें कि कोटा क्षेत्र के कई गांवों में

डायरिया के सैंकड़ों मरीज मिल चुके हैं।जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है।जैसे तैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डायरिया को कंट्रोल किया था।लेकिन अब कोटा क्षेत्र में मलेरिया के केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप है।

इस बार टाटीधार गांव में मलेरिया के चार मरीजों की पुष्टि हुई है। इसकी सूचना मिलते हैं विभाग में हड़कंप मच गया है। तत्काल डॉक्टरों की टीम भेजकर गांव में कैंप लगवाया गया है। गांव में मिले मरीजों में शिवम नाम के एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। मलेरिया के साथ मरीज में पीलिया की भी पुष्टि हुई है।

सीएमएचओ प्रभात श्रीवास्तव ने कहा कोटा क्षेत्र के टाटीधार में मलेरिया के तीन चार मामले सामने आए हैं। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर सिम्स अस्पताल भेजा गया है।

आपको बता दें कि गंभीर रूप से बीमार युवक को संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से सिम्स अस्पताल में भेजा गया है।फिलहाल डॉक्टरों की टीम ने गांव के कई लोगों का मलेरिया टेस्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग अब हर बुधवार को गांव के हर एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेकर मलेरिया टेस्ट करेगा।

पामगढ़ में डायरिया का प्रकोप, 80 से अधिक ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, कोसीर गांव में लगा शिविर

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोसीर में डायरिया से 80 से अधिक ग्रामीणों की तबियत बिगड़ी है। नल जल योजना से घर में लगे नल का पानी पीने से तबीयत खराब हुई है। पामगढ़ सीएचसी अस्पताल में 35 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी ग्रामीण जिला अस्पताल जांजगीर और बिलासपुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। गांव में 3 दिनो का स्वस्थ शिवर भी लगाया गया है। पामगढ़ सीएचसी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे मरीजों से बात करने पर पता चला कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांव में नल लगाया गया जिसमे से पानी पीने के बाद रात को उल्टी और दस्त होने लगी यह गांव के कई घरों के लोग बीमार पड़े है। जिसमे 80 से अधिक लोग शामिल है। अभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। सीएचसी अस्पताल के डॉ.सौरभ यादव ने बताया कि डायरिया से पीड़ित 35 मरीजों को उल्टी दस्त होने की शिकायत है। जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। डायरिया से बीमारी होने पर गांव कोसीर जाकर निरीक्षण किया गया। गांव में 3 दिवसीय स्वस्थ शिविर भी लगाया गया है। टेप नल की पानी पीने से तबियत बिगड़ी है जिसमे पटेल पारा ओर यादव पारा में ज्यादा मरीज है। पीएचई विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है।

कबीरधाम जिले में जलस्त्रोतों का क्लोरिनेशन और स्वच्छता अभियान शुरू

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर सभी सार्वजनिक और निजी जल स्त्रोतों का क्लोरिनेशन और स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। जिले के सभी सार्वजनिक एवं निजी जल स्त्रोतों की स्वच्छता के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य अमला और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी है। इसके लिए जिले के सभी विकासखण्डों में पांच-पांच दल गठित किए गए हैं, जो क्लोरिनेशन का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और ग्राम स्तर पर मितानिनों को भी इस कार्य में शामिल किया गया है।

जिले के विकासखण्डों में कुल 13,538 जल स्त्रोतों, जिसमें कुएं, हैण्डपंप, सोलर पंप आदि शामिल हैं, का क्लोरिनेशन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में भी स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने इस कार्य के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य अमला और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी है। इसके लिए जिले के सभी विकासखण्डों में पांच-पांच दल गठित किए गए हैं, जो क्लोरिनेशन का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और ग्राम स्तर पर मितानिनों को भी इस कार्य में शामिल किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और सिटी बस के बीच जोरदार भिड़ंत

रायपुर। राजधानी रायपुर में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक और सिटी बस में आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा विधानसभा थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव के पास हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस समेत आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार, बस रायपुर से खरोरा की ओर जा रही थी। वहीं ट्रक सामने से आ रहा था। इस बीच सेमरिया गांव के पास तेज रफ्तार बस चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। इसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में सवार कई यात्रियों को काफी चोटें आई है।

राजधानी के महापौर आरक्षण के लिए होगी लॉटरी

रायपुर। राजधानी के 70 वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। इसी के साथ शहर में निगम चुनाव को लेकर हलचल भी बढने लगी है। यह तय माना जा रहा है कि भाजपा सरकार रायपुर समेत सभी निगमों में शहरी सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस निकाय चुनाव के बहाने अपनी कुर्सी निगम व पालिका में बचाने की कोशिश करेगी। राजधानी के महापौर आरक्षण के लिए लॉटरी होगी क्योकि वार्डों का परिसीमन हो रहा इसलिए इस बार सामान्य वर्ग की भी पर्ची शामिल रहेगी।

स्कूल रेडिनेस के तहत खेल-खेल में सीखने का हुआ प्रशिक्षण

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम- ग्रेड 1 के बच्चों के लिए 3 माह का खेल आधारित शाला तैयारी के कक्षा संचालन, शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में वर्तमान शिक्षा सत्र हेतु पढ़ाने वाले शिक्षकों के 4 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण एससीईआरटी छत्तीसगढ़ रायपुर के संचालक, श्री राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन में दिया गया। बच्चे खेल-खेल में 3 माह में सीखेंगे और साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से तीन लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया जिस पर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, बच्चों में प्रभावशाली संप्रेषण बनना और बच्चों को सीखने के प्रति उत्साह और पर्यावरण से जुड़ाव की बातें कही गई है। यह शिक्षण पद्धति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है, जिसे बच्चों को 3 महिनें में प्राप्त करना होगा।

विश्व सर्प दिवस पर डाक विभाग ने पिक्टोरियल पोस्टकार्ड का किया अनावरण

रायपुर। भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पिक्टोरियल पोस्टकार्ड एवं कैन्सलेसन कैचेट का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छग (पी सी सी एफ) श्री सुधीर अग्रवाल, छ ग डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्रीमती वीणा आर. श्रीनिवास एवं निदेशक डाक सेवाये श्री दिनेश कुमार मिस्त्री उपस्थित थे। समारोह मे छ ग के विभिन्न पर्यावरणविद, वन्य जीव संरक्षक एवं फिलैटलिस्ट भी उपस्थित थे। पिक्टोरियल पोस्टकार्ड मे सांपों की 24 प्रजातियों के सेट में से 10 प्रजातियों को आगमेंटेड रेयालिटी फीचर्स के साथ जारी किया गया। इस समारोह के द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सांपों के योगदान के बारे मे चर्चा की गई एवं उनके संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया।

राज्य में लक्ष्य का 59 प्रतिशत बोनी पूर्ण

रायपुर। चालू खरीफ सीजन में अब तक लक्ष्य का 59 प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुका है। जबकि इस सीजन के राज्य सरकार द्वारा 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों के बोनी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 28.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है।

9.57 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद किसानो को वितरित

रायपुर। प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 15 जुलाई 2024 की स्थिति में किसानों को 9 लाख 57 हजार मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का वितरण किया जा चुका हैं,जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत है। वितरित किए गए उर्वरक में 4 लाख 56 हजार 319 मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 23 हजार 600 मीट्रिक टन डीएपी, एक लाख 13 हजार 544 मीट्रिक टन एनपीके, 33 हजार 372 मीट्रिक टन पोटाश तथा एक लाख 15 हजार 590 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट का वितरण शामिल है। चालू खरीफ सीजन के लिए राज्य में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को 13 लाख 68 हजार मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध अब तक 13 लाख 48 हजार मीट्रिक टन का भण्डारण करा लिया गया है। भण्डारण के विरूद्ध 9.57 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद का वितरण सोसायटी और निजी विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खाद बीज वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

डिप्टी सीएम साव ने डायरिया और गौ हत्या मामले में विपक्ष पर लगाया आरोप

■ कहा- मौत पर राजनीति करती है कांग्रेस

रायपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने गौ तस्करी पर बनाए गए नए नियम को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। उपमुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह मौत पर राजनीति करती है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से राजनीति करती रही है। तथ्य और वस्तु स्थिति जाने बिना भ्रम फैलाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बार-बार इन्हें परखा है। कांग्रेस ने जनता के हितों की खिलाफ जाकर अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी की यही चाल और चरित्र है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।

डिप्टी सीएम साव ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की है। उनके अपने लोग गौ तस्करी में शामिल थे। सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रही थी लेकिन हमारी सरकार गौतस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबंध है, इसलिए यह नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम

साव ने गौ तस्करी मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

वहीं आगामी विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के हित में निर्णय लेकर काम कर रही है और विपक्ष को हर मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए है। सदस्य अपने मुद्दे उठाएं, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है।

उपमुख्यमंत्री साव ने प्रदेश के नगरी निकायों को मिलने वाले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को पांच पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। सूडा के साथ चार नगरी निकाय को पुरस्कार मिलेगा। स्वरोजगार, आजीविका और शहरी रोजगार की दिशा में यह पुरस्कार मिलने जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। विभागीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सम्मान के लिए आभार है।

धनेन्द्र साहू ने डिप्टी सीएम के बयान का किया पलटवार

वहीं डीसीएम अरुण साव के कांग्रेस मौत पर राजनीति करती है वाले बयान पर विपक्ष के धनेन्द्र साहू ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, डायरिया से हुई मौतों को छुपाने षड्यंत्र हो रहा है। भाजपा ज़िम्मेदारी न लेना पड़े, इसलिए झूठी रिपोर्ट देकर जनता को गुमराह कर रही है। बीमारियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी किया जाना चाहिए था। ये दायित्व निभाने में फेल है और आरोप कांग्रेस पर लागा रहे हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले: कश्यप

बीजापुर। वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्री तथा बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य और केन्द्र प्रवर्तित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप कहा कि शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधों का सहयोग लिया जाए।

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले के विषम परिस्थिति के बावजूद विभागीय समन्वय के साथ विकास कार्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिकारियों का उत्साहवर्धन भी किया। बैठक में बस्तर लोकसभा सांसद श्री महेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित थे।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि बरसात के मौसम में मौसमी एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया उन्मूलन के लिए मच्छरदानी वितरण, डीडीटी छिड़काव सुनिश्चित करें। सर्पदंश के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में एन्टी वेनम व अन्य मेडिसिन की व्यवस्था रखी जाए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की उन्नति के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर ही है। शासन द्वारा किसान हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन की जा रही है।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश को आज मिलेंगे 5 राष्ट्रीय पुरस्कार

बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन स्पार्क-2023-24 पुरस्कार के लिये

■ केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू देंगे पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना ङ्क राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में 18 जुलाई को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क-2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में

उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और चारों नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।

भारत सरकार द्वारा स्पार्क-2023-24 पुरस्कार के लिए चयनित सूडा, बिलासपुर व रायगढ़ नगर निगम तथा चांपा व भाटापारा नगर पालिका के अधिकारियों और लाभार्थियों की कुल 20 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ की ओर से नई दिल्ली में ये पुरस्कार ग्रहण करेगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है।

रायपुर डाक संभाग के उप डाकपाल और डाक सहायकों के तबादले

रायपुर। वरिष्ठ डाक अधीक्षक एच के महावीर ने रायपुर डाक संभाग के दो दर्जन (25) उप डाकपाल और डाक सहायकों के तबादले किए हैं। इनमें से 10 स्वयं के आग्रह पर स्थानांतरित किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार वीपी गोस्वामी धमतरी से कलेक्टोरेट, सीमा बेदी कलेक्टोरेट से धमतरी एमडीजी, संजय पाठक दयानंद नगर से गुढियारी, पीएल चक्रधारी गुढियारी से संभागीय कार्यालय, सोनिया सोनी कृषक नगर से टाटीबंध, ओपी कश्यप मंत्रालय से सुंदर नगर, अनिल कुमार सिंह रायपुर गंज से रविग्राम, अरूणा शाह रविग्राम से दयानंद नगर, सीएस सिंह सुंदर नगर से उरला, यूके मिश्रा सड्डु से मुख्य डाकघर, एलएन सिंह टाटीबंध से डब्ल्यूआरएस, पतिराम टेकाम उरला से मुख्य डाकघर, पुष्पा कुजूर डब्ल्यूआरएस से मुख्य डाकघर, समीर देवांगन मुख्य डाकघर से संभागीय कार्यालय, परमेश्वरी महाजन पीएसडी से संभागीय कार्यालय, टीएस सार्वा रविशंकर से सड्डु, यूके भोई मुख्य डाकघर से गंज, सीमा सोनी मुख्य डाकघर से कृषक नगर, आलोक मरकाम मुख्य डाकघर से सीबीएस रायपुर, मोहम्मद जावेद खान सीबीएस से मंत्रालय।

इसी तरह से टीएल वर्मा बैकुंठ से तिल्दा-नेवरा, दीपक चौधरी यथावत, मनोज देवांगन छोटापारा से रविग्राम, संतोष साहू धमतरी से नगरी, मोहनलाल साहू गुढियारी से कचहरी, युवराज यादव नगरी से बिलईगढ़, किरण देवांगन पंडरी से मुख्य डाकघर, ललित साहू गंज से संभागीय कार्यालय, श्रीराम साहू रविग्राम से गुढियारी, शिवनाथ देवांगन राजिम से धमतरी, सौरभ सिंह तिल्दा-नेवरा से बैकुंठ, सुरेन्द्र सिंह बाघमारे शंकर नगर से गंज, दीपक एक्का सराईपाली से भटगांव, दिनेश साहू मुख्य डाकघर से सुंदरनगर, डीपी वर्मा मुख्य डाकघर से पंडरी, कविता महेश श्रीसाले मुख्य डाकघर से दयानंद नगर, मनीषा बी मुख्य डाकघर से छोटापारा, पार्वती मुख्य डाकघर से संभागीय कार्यालय, सुदर्शन यादव मुख्य डाकघर से बीरगांव, भूपेन्द्र चंद्राकर संभागीय कार्यालय से शंकर नगर, प्रेम सिंह क्षत्रिय यथावत, अभिषेक साहू संभागीय कार्यालय से राजिम, गणपत पटेल यथावत, किरण लता देवांगन मुख्य डाकघर से रविशंकर, टीआर डहारे मुख्य डाकघर से पीएसडी शामिल है।

रविवि ने निकली 194 पद पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कई सालों से नहीं हुई है जबकि, पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाठ्यक्रम की पढाई सुचारू रूप से चलाने के लिए विवि ने अतिथि व्याख्याता की भर्ती करने का निर्णय लिया। विवि प्रबंधन 194 पद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के पद निकाले हैं, जिसमें 27 प्रोफेसर, 52 एसोसिएट प्रोफेसर और 115 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इसके अलावा दो अतिथि ग्रंथपाल की भी भर्ती विवि ने निकाली है। इन्हें 30 से 40 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। सभी पदों के लिए विवि ने 22 जुलाई तक आवेदन मंगाए है। आवेदन पत्र विवि की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन केवल बंद लिफाफे में विवि के कुलसचिव के नाम कूरियर या स्वयं के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। विवि के उप कुल सचिव (सामान्य प्रशासन) अनिमेष देवांगन ने बताया कि रविवि में वर्ष 2017 से व्यायाताओं की भर्ती नहीं हुई है। तीनों श्रेणी के प्राध्यापकों के 130 नियमित पद खाली है। विवि में प्रोफेसर, एसोसिऐट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के कुल 220 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 90 भरे हैं जबकि कई बार विवि प्रबंधन नियमित भर्ती के लिए शासन को पत्र लिख चुका है। अतिथि व्यायाताओं की भर्ती में विवि में कार्यरत पुराने अतिथि व्यायाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भर्ती शासन की ओर से बनाए गए अतिथि व्यायाता नियम 2024 के नियमानुसार की जाएगी। पहले से कार्यरत अतिथि व्यायाताओं को अपने विभागाध्यक्ष के ओर से जारी मूल्यांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विवि में नियमित प्रोफेसर के तीनों श्रेणी के पदों को बढ़ाने के लिए भी शासन को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि लगभग 140 अतिथि व्यायाता तीनों श्रेणी के विवि में पहले से कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि सत्र 2024-25 में विवि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के साथ कई नए कोर्स शुरू हुए हैं जिसमें एमए सिंधी भाषा, फॉर्मेसी में चार नए कोर्स, चार वर्षीय बीए, बीकॉम, बीएससी. बीएड, मास्टर ऑफ होटल मैनेंजमेंट और मास्टर ऑफ कामर्स शामिल हैं। इन कोर्स के शुरू होने से लगभग 400 सीटें विवि में बढ़ी है लेकिन पढ़ाने के लिए व्यायाताओं की एक भी भर्ती नहीं की गई। इस कारण अतिथि व्यायाताओं की भर्ती के पद निकाले गए हैं।

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन का बड़ा बयान

■ कहा- गुंडे-मवालियों पर होना चाहिए शासन-प्रशासन का भय, वारदातों पर लगे लगाम

रायपुर। प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस के आरोपों के बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि राजधानी के गुंडे, मवालियों पर शासन-प्रशासन का भय होना चाहिए। जो वारदातें हो रही हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गृह विभाग की बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। राजधानी के गुंडे-मवालियों पर शासन-प्रशासन का भय होना चाहिए। जो वारदातें हो रही हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रायपुर के सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक समस्या है। इसके निदान पर भी काम होना चाहिए।

वहीं भाजपा की कुठित कांग्रेस वाले पोस्ट पर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस आउटगोइंग पार्टी हो गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मार खाने के बाद कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेसी अब बिना जल के मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बंद हो गया है, पैसा आना बंद हो गया है।

दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि दीपक बैज पहले अपनी सरकार की बात करें। मुख्यमंत्री उनके सुनते नहीं थे। अभी भी क्या चल रहा है, दोनों में पहले उन्हे क्लियर करें।

चार माह नहीं होंगे शुभ मांगलिक कार्य

रायपुर। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद अगले चार महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में ही रहते हैं, इसलिए किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की योग निद्रा के काल को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाना चाहिए। इससे उनकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहायक ग्रेड-3 पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 03 पद हेतु प्रथम स्तर के लिखित परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केन्द्र बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर आवेदक द्वारा सहायक ग्रेड-3 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। व्यापम के वेबसाईट पर परीक्षा के लिए पंजीयन व जिला चयन की प्रारंभिक तिथि 2 जुलाई तथा अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है।

नियंत्रक व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा केन्द्र जिला के चयन के

आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 22 जुलाई को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन नहीं किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

डोडा एनकाउंटर पर ओवैसी को सीएम साय का जवाब

कहा- दुनिया देखी है किस तरह घर में घुस कर मारे हैं

रायपुर। जम्मू कश्मीर के डोडा एनकाउंटर में आतंकी हमले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक बना हुआ है। डोडा आतंकी हमले में शहीद जवानों पर एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि डोडा हमले की पूरी जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी की है। दहशतगर्दी पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने कहा

कि पीएम मोदी कहते हैं घर में घुस कर मारेंगे, अब कहां है?

ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि किस तरह घर में घुस कर मारे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। सीएम साय ने ये बातें रायपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने के दौरान कही।

डोडा आतंकी हमले में जम्मू के डोडा जिले के देसा वन क्षेत्र में सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन सहित चार जवान शहीद हो गए। देश के लिए अपनी प्राणों की आहूति देने वाले वीर जवानों में कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय कुमार सिंह है।

सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम साय और डिप्टी सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और रेल राज्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। सीएम के दिल्ली दौरे से साय कैबिनेट का विस्तार और प्रदेश के लिए नई ट्रेनें चालू करने की अटकलें तेज हो गई है।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER MAHANADI GODAWARI BASIN RAIPUR (C.G.)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(3rd CALL)

System Tender No.: 155566/NIT No.: 01/SAC/2024-25. Kawardha, Dated: 04.07.2024

Online Tenders are invited for the following works up to 22.07.2024 at 17.30 Hour

Name of work: BAKELA DIVERSION FEEDER CANAL FROM RD 8400 TO 13380 M AND CONSTRUTION OF I NOS FALL, 8 NOS V.R.B., 9 NOS C.D., I NOS SYPHON AND I NOS OF CANAL CROSSING OF BAKELA FEEDER CANAL AT BLOCK PANDARIVA DISTRICT KABIRDHAM

Probable Amount of Contract: **Rs. 499.41 Lakhs**
(As per S.O.R Dated 01.08.2010 (As amended dated 22.08.2022))

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal **(https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 11.07.2024, at 17.31 Hours. (IST) onwards.**

NOTE:- All eligible/intrested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e procurement portal **(https://eproc.cgstate.gov.in)** and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Executive Engineer
Water Resources Division, Kawardha
Disst. Kabirdham (C.G.)
For, Chief Engineer, Mahanadi
Godavari Basin Raipur (CG)

जी-242501112/9

यूरोप के सामने पहचान की चुनौती

प्रभु चावला

वर्तमान यूरोप में अतीत ही भविष्य है। लगभग 13 सौ साल पहले युद्ध से यूरोप के धार्मिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश हुई थी। आठवीं से दसवीं सदी के बीच उम्मयद शासकों ने स्पेन, पुर्तगाल, सिसिली और माल्टा को जीतकर यूरोपीय इतिहास को नया मोड़ देने की कोशिश की, पर वे इन दक्षिणी सीमाओं से आगे नहीं जा सके। ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड क्रीजी ने 19वीं सदी में लिखा था कि चार्ल्स मार्टेल की महान जीत ने पश्चिमी यूरोप में अरबों की जीत को निर्णायक रूप से रोका, इस्लाम से ईसाइयत को बचाया तथा प्राचीन अवशेषों एवं आधुनिक सभ्यता के स्रोतों को संरक्षित किया। हाल में ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। नयी संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या 19 से बढ़कर 25 हो गयी है। फ्रांस में इस्लाम-विरोधी, प्रवासन-विरोधी राष्ट्रवादी दक्षिण को वामपंथी पार्टियों के गठबंधन ने हरा दिया है। उसके बाद वहां फसाद भी हुए। दूसरी ओर, स्विटजरलैंड, इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक में राष्ट्रवादियों को जनादेश मिला है। स्वीडन की संसद में दक्षिणपंथी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नीदरलैंड में इस्लाम-विरोधी नेता गीर्ट वाइल्डर्स चार दलों के गठबंधन के नेता हैं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी जैसी दक्षिणपंथी नेता यूरोप में शरिया-विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। हार के बावजूद फ्रांस में ले पेन डटी हुई हैं। मध्य युग में जो युद्ध पीछे धकेला गया था, वह वापस लौटता प्रतीत हो रहा है। शब्दों के हथियारों से लड़ने वाली सेनाओं के नये नाम इस प्रकार हैं- कॉमी, वोक, एंटी-सेमिटिक, इस्लामोफोब, नियो नाजी आदि। खैर, आप जहां भी हों, लोकतंत्र रैडिकल इस्लाम के लिए मध्यकालीन सेनाओं से बेहतर साधन साबित हो सकता है। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स 2024 के अनुसार, पश्चिम में ब्रिटेन मुस्लिमों के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। फिर भी सर्वे बताते हैं कि 40 प्रतिशत ब्रिटिश मुस्लिम शरिया को कानून बनाना चाहते हैं। फ्रांस में 'स्वतंत्रता' जेहादियों और उनके समर्थकों के लिए है, 'समता' हत्यारों के लिए है तथा 'बंधुत्व' उस धर्म के लिए है, जो चर्चों को मस्जिद बनाना चाहता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें लगता है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और शारीरिक सुरक्षा पर खतरा है। यूरोप में हर जगह उन्मादी हमले का जोखिम है। लोग भयभीत हैं। साल 2014 के एक सर्वे में पाया गया था कि 57 प्रतिशत जर्मन इस्लाम को खतरा मानते हैं, 61 प्रतिशत का मानना है कि इस्लाम और पश्चिम साथ नहीं चल सकते, 40 प्रतिशत लोग मानते है कि इस्लाम के चलते वे अपने ही देश में अजनबी जैसा महसूस करते हैं तथा 24 प्रतिशत मुसलमानों को जर्मनी नहीं आने देना चाहते हैं। ब्रिटेन में 2012 के एक सर्वे में पाया गया था कि 49 प्रतिशत लोग आशंकित है कि ब्रिटिश मुस्लिमों और गोरे अंग्रेजों में सभ्यतागत युद्ध होगा। ये वही लोग हैं, जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह हरा दिया है। साल 1291 में रोमन कैथोलिक चर्च के तबाह होने के साथ जेरूसलम को इस्लामी नियंत्रण से छीनने के धर्मयुद्धों का अंत हो गया था। महान इस्लामी योद्धा सलादीन को ब्रिटिश शासक रिचर्ड प्रथम ने हरा दिया था। दोनों में हुए समझौते से लेवांत क्षेत्र में ईसाइयत के अस्तित्व को एक सदी का समय और मिल गया। सलादीन उदार था, पर अब उसके कम उदार धार्मिक वंशज ब्रिटेन की मदद से ही ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति ने ब्रिटिश नेताओं को समझौता करने वाली की पीढ़ी में बदल दिया है। ऋषि सुनक इस कारण भी हारे कि वे प्रवासन पर स्पष्ट नहीं थे और धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी ने उस खेमे के वोटों को बांट दिया। मुस्लिम अपनी धार्मिक पहचान पर अडिग रहते हैं। मुस्लिम आबादी 2011 में 4.9 प्रतिशत थी, जो 2021 में 6.5 प्रतिशत हो गयी। मस्जिदों की संख्या एक दशक में दुगुनी हो गयी है।

मुस्लिमों को कूपमंडूक बनाए रखना चाहते हैं विपक्ष

योगेंद्र योगी

गैरभाजपा राजनीतिक दलों में विशेषकर कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उनके अधिकारों को लेकर कभी भी पहल नहीं की। यही वजह रही कि देश का मुस्लिम वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल होने से पिछड़ गया। इतना ही नहीं गैरभाजपा दलों ने जब कभी मुसलमानों की भलाई का मौका आया तब नजरें चुरा ली बल्कि सत्ता में आने पर पुरानी स्थिति बहाल करने तक का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम महिला को पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की याचिका थी। कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 की मदद ले सकती हैं। यह कानून सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया।

इस फैसले को गैरभाजपा दल गले नहीं उतार पा रहे हैं। इसी तरह तीन तलाक के फैसले को लेकर कांग्रेस सहित दूसरों दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को पलट कर वापस तीन तलाक लागू करने का वादा किया था। इससे पहले शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कानून में संशोधन करके बदल दिया था। कांग्रेस ने यह सब किया वोट बैंक की खातिर, किन्तु वह भी बच नहीं सका। दूसरे दल मुसलमानों की भलाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में ज्यादा आगे निकल गए। गैर कांग्रेस दलों में प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों की खातिर आतंकवाद के आरोपियों से समझौता तक करने में गुरेज नहीं किया।

शाह बानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर कोर्ट का फैसला बदल दिया था। शाह बानो ने 1978 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिया जाए। साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल को अपनी तलाकशुदा बीवी को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का कहा गया था। समद ने अपनी बीवी को तीन तलाक दिया था। इसके जवाब में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 लागू कर दिया। इस अधिनियम ने तलाक के बाद केवल 90 दिनों तक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरह मुस्लिमों की आधी आबादी के पक्ष में जब तीन तलाक को निरस्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया तब भी गैरभाजपा दलों ने काफी हायतौबा मचाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है। तीन तलाक के मुद्दे पर गैरभाजपा दलों का असली चेहरा तब सामने आया जब संसद में इसके मामले में कानून पास करने से पहले वोटिंग हुई। गैरभाजपा दल ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, लेकिन राज्यसभा से वोटिंग के पहले भाग गए। इनमें बसपा के 4, सपा के सात, एनसीपी के 2, पीडीपी के 2, कांग्रेस के 5, टीएमसी, वामपंथियों पार्टियों, आरजेडी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस के एक-एक सांसद अनुपस्थित रहे। बिल को पास कराने के लिए एनडीए को 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए था, लेकिन सांसदों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की वजह से सदन में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और वह बिल पास कराने में सफल रही। विपक्ष के भागने की वजह यह रही कि भाजपा इसे मुद्द बना कर मुस्लिम महिलाओं से उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन नहीं करवा दे।

बिल पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई ने कहा कि बिल का मैं 6 कारणों से विरोध करता हूं। लेकिन वोटिंग के दौरान विजय साई सदन में अनुपस्थित थे। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का कहना था कि हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है और आप फिर से इसे अस्तित्व में लाना चाहते हैं। इस बिल से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली हैं क्योंकि पुरुष के जेल जाने के बाद महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। सरकार ने बच्चों की देखरेख करेगी और न महिलाओं को गुजारा भत्ता देगी, ऐसे में उनका जीवन कैसे चलेगा। तीन तलाक पर इस तरह मुखर होने के बावजूद बसपा का कोई सांसद सदन में उपस्थित नहीं था।

एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कहा कि आप किसी को बगैर अपराध के 3 साल की सजा देने जा रहे हैं, तलाक कहना कोई अपराध नहीं है। जेल में जाने के बाद भी शादी खत्म नहीं होगी और महिला को गुजारा भत्ता के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। जेल में रह रहा पति कैसे पत्नी को भत्ता दे पाएगा, ऐसे में कानून फेल हो गया। यह बिल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। मगर जब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए सदन में वोटिंग हो रही थी, उस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित नहीं थे। तीन तलाक बिल का विरोध करने वाले एनडीए के सहयोगी दल तो वॉकआउट कर गए जिनमें अन्नाद्रमुक, जेडीयू शामिल हैं। गैर-एनडीए और गैर-यूपीए टीआरएस सदन में गैर मौजूद रही।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की एक साजिश है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता एक लफ्ज तक नहीं बोला।

तीन तलाक पर पाबंदी का फैसला हो या मेंटीनेंस पाने का हक, मुस्लिम आधी आबादी लंबे अर्से से अपने अधिकारों के प्रति अंधेरे में रही है। उलेमाओं और मौलवियों ने ऐसे अधिकारों का हमेशा से विरोध किया है। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की पैरवी की है। यदि ये दोनों अधिकार कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर मुहैया करा देती तो आज देश में मुसलमानो के विकास की सूरत अलग होती। किसी भी शिक्षित और जागरुक कौम को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। गैरभाजपा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जागरुक करने और शिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यहां तक मुसलमानों के खैरख्वाह बनने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया। यही वजह रही आजादी के बाद जितनी तरक्की मुसलमानों को करनी चाहिए थी, उसकी तुलना में पिछड़ गए।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उप-पुराण (भाग-5)

गतांक से आगे...

श्रीमद्भागवत में पुरुष प्राधान्य से और देवी भागवत में प्रकृति प्राधान्य से उस एक ही जगन्नियन्ता का वर्णन किया गया है; अत: दोनों के सम्मिलित कर देने पर एक पूरा पुराण बनता है।

शायद वेद पारायणी पाठकों को यह तो बताने की आवश्यकता न हो कि वेद, गणना में दूसरे वेद को %यजुर्वेद% के नाम से गिना जाता है, परन्तु यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण नाम के दो भेद हैं जो भिन्न-भिन्न पुस्तकाकार में उपलब्ध होते हैं। अपनी 2 शाखा के अनुसार खास 2 देशों में शुक्ल संहिता का और किन्हीं देशों में कृष्ण संहिता का अधिक प्रचार है। भाष्यकारों ने भी अपनी 2 शाखानुसार किसी एक पर ही भाष्य किया है, यथा सर्ववेद-भाष्यकार सायण ने कृष्णयजुर्वेद पर ही भाष्य रचा है। उव्वट तथा महीधर ने केवल शुल्क यजुर्वेद पर।

आर्य- समाज भी शुक्लवेद का ही विशेष आग्रही है, तथापि वैदिकं सिद्धान्त में मान्यता और सांप्रदायिकता को तथैव सुस्थिर रखते हुए निरनुबन्ध-यजु: शब्द से दोनों भेदों को अविशेष एक वेद ही माना गया है।

उक्त भेदों के कारण न तो वेदों को पांच बनाने का प्रयास किया जाता है और नाँहीं पारस्परिक भेदभाव का आरोप किया जाता है। ठीक इसी प्रकार की भागवत के दोनों भेदों की समस्या है। इससे अधिक कुछ कहना अनावश्यक है।

जिस प्रकार शिव-पुराण का दूसरा नाम वायु-पुराण है इसी प्रकार अन्तिम ब्रह्माण्ड-पुराण की भी किसी 2 स्थान पर वायु-पुराण संज्ञा है, यहाँ भी दोनों को पृथक् 2 गिन कर पुराणों की संख्या को 16 बताने का साहस किया जाया करता है, परन्तु यह पुराण भी ब्रह्मा जी से वायु ने प्राप्त किया और आगे ऋषियों के प्रति कथन किया है।

क्रमश: ...

नेल्सन मंडेला के वह बड़े कार्य, जिनकी बदौलत पूरी दुनिया में मिला सम्मान

सुधांशु

दुनियाभर में जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी सम्मान दिया है। इसलिए 18 जुलाई को प्रतिवर्ष उनकी जयंती को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर लोगों को शांति, रंगभेद, गरीबी, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गयी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद इस दिन को पहली बार 18 जुलाई 2010 को औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया गया है। तबसे लेकर अब तक प्रतिवर्ष यह दिन 18 जुलाई को मनाया जाता है।

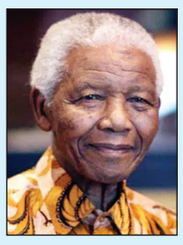

दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला ने न केवल देश से नस्लवाद खत्म किया बल्कि गोरे शासन के दौरान दमन से गुजरे अश्वेतों के गुस्से की वजह से उस मौके पर वह हिंसा नहीं होने दी जिसकी आशंका जतायी जा रही थी।

दक्षिण अफ्रीका में जब 1994 में नस्लवाद खत्म हुआ तब ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी व्यापक हिंसा होगी। दरअसल गोरे शासन में दमन की इंतहा हो गयी थी और ऐसा माना जा रहा था कि नस्लवाद के खात्मे के बाद श्वेतों के खिलाफ अश्वेत लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा एवं व्यापक हिंसा होगी लेकिन मंडेला ऐसे करिश्माई व्यक्ति थे कि हिंसा की एक भी घटना नहीं होने दी।

मंडेला ने वर्ष 1952 में अनुचित कानूनों के खिलाफ व्यापक नागरिक अवज्ञा अभियान डिफियांस कैम्पेन शुरू किया। उन्हें इस अभियान का प्रमुख स्वयंसेवक चुना गया। सन् 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध के बाद मंडेला ने उसकी सशस्त्र शाखा बनाने की वकालत की। जून 1961 में एएनसी इस बात पर सहमत हुई कि जो लोग मंडेला के अभियान से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगी। उसके बाद उमखांतो वी सिजवे की स्थापना हुई और मंडेला उसके कमांडर इन चीफ बने। मंडेला को 1962 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें पांच साल का कठोर कारावास मिला। सन् 1963 में एएनसी और उमखांतो वी सिजवे के कई नेता गिरफ्तार किए और मंडेला समेत इन सभी पर हिंसा के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का मुकदमा चला। बारह जून, 1964 को मंडेला समेत आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इन सभी को पहले रोब्बेन द्वीप और बाद में विक्टर वर्स्टर जेल ले जाया गया। जेल के दौरान मंडेला की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण अश्वेत नेता माना जाने लगा। उन्होंने जेल से रिहाई के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति से कोई समझौता करने से इंकार कर दिया। नस्लवाद के खिलाफ लंबे समय तक जनांदोलन चलने के बीच एएनसी ने सरकार से वार्ता शुरू की। उसी बीच 1990 में मंडेला को रिहा कर दिया गया। सन् 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

अमेरिका में बढ़ गया है राजनीतिक विभाजन

अनिल त्रिगुणायत

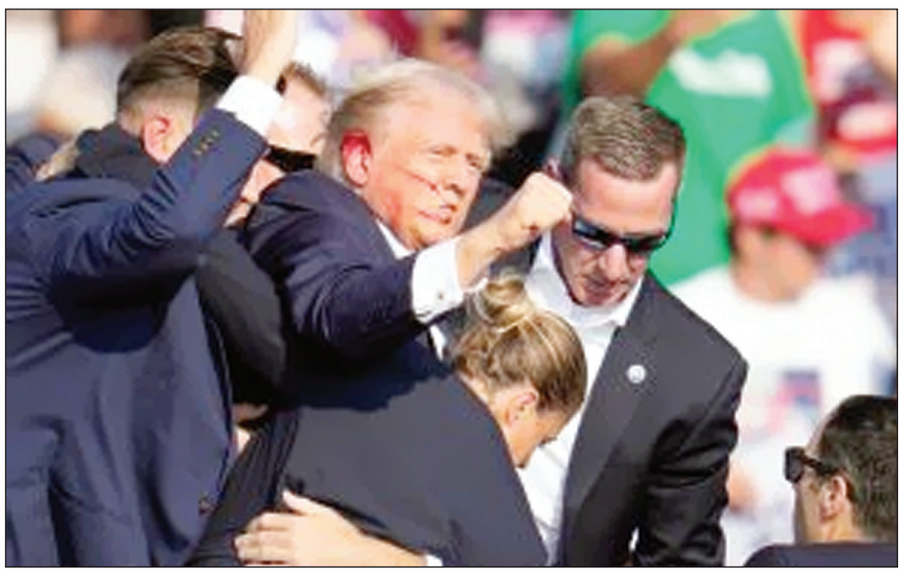

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और इस बार के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की पूरी जांच होने के बाद ही हमें हमलावर के इरादों के बारे जानकारी मिल सकेगी, पर यह सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का नतीजा तो है ही। इस घटना से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमेरिकी समाज और राजनीति में भारी विभाजन हो चुका है। पिछले चुनाव में जब राष्ट्रपति ट्रंप हार गये थे, तो हमने देखा कि अमेरिकी कैपिटल, जो वहां की संसद है, पर भीड़ का हमला हुआ था। तब ट्रंप ने एक तरह से उनका समर्थन किया था और कैपिटल मार्च का आह्वान भी किया था। आज तक उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है कि 2020 का चुनाव वे हार गये थे। भले ही अमेरिका अपने को महानतम लोकतंत्र की संज्ञा दे, पर राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण आसान नहीं रह गया है। कैपिटल हमले के बाद भी राजनीतिक विभाजन को पाटने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गयी। यह जगजाहिर तथ्य है कि अमेरिका के रोजमर्रा का जीवन हिंसक घटनाओं से भरा पड़ा है। आये दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं, कभी स्कूल में, कभी सड़क पर, तो कभी शॉपिंग मॉल में सरफिरे अंधाधुंध गोलियां चलाकर बहुत से लोगों की जान ले लेते हैं। अमेरिका में 'गन लॉबी' बहुत ताकतवर है और हिंसक माहौल बनाने में उसकी भी एक भूमिका है।

अमेरिका में दो पार्टियां हैं- रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। वर्तमान राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन अधिक उम्र में होने वाली समस्याओं से घिरे हैं और इसके कारण उनकी लोकप्रियता बहुत घट गयी है। उनके बरक्स ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी है। हालिया हमले के बाद ऐसा लगता है कि जो मध्यमार्गी मतदाता हैं, जो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हैं और वैसे रिपब्लिकन, जो ट्रंप को लेकर आश्वस्त नहीं थे, ये लोग अब ट्रंप को समर्थन देंगे। घटना के बाद बाइडेन ने राजनीतिक तनातनी कम करने का जो आह्वान किया है, वह स्वागतयोग्य है। किसी भी लोकतंत्र में जब राजनीतिक विमर्श हिंसक हो जाता है, तो उससे लोकतंत्र को ही नुकसान होता है, वह समाज के लिए घातक हो जाता है।

हमले के क्षण भर बाद ट्रंप ने घायल होने के बाद भी जिस प्रकार से मुट्ठी बांधकर 'फाइट, फाइट' की बात कही, वह चित्र अब एक प्रतीक बन गया है। उसके बाद वे रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में गये, जहां आशा के अनुरूप औपचारिक रूप से उन्हें पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। वहां उन्होंने ओहायो के सीनेटर जेडी वैन्स को बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। यहां थोड़ा भारतीय आयाम यह है कि वैन्स की पत्नी भारतीय मूल की हैं। दोनों ने येल विश्वविद्यालय में साथ पढ़ाई की है।

अमेरिकी चुनाव के मतदान में चार महीने बचे हैं। इस अवधि में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन खत्म होने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वहां बहुत अधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है। वहां की राजनीतिक संस्कृति में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति डेमोक्रेट या रिपब्लिकन होता है, वह जीवनभर अपनी पार्टी का समर्थक बना रहता है। ऐसे बहुत कम लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को छोड़कर विरोधी पार्टी के लिए मतदान करते हैं। अगर नेता या समर्थक सार्वजनिक रूप से हिंसा की बात करेंगे, तो हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक ही है। हालांकि दोनों नेताओं ने शांति की अपील की है, पर अमेरिकी समाज बहुत अधिक सशस्त्र है। अमेरिका में लोगों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है। अधिकतर नागरिकों के पास बंदूकें हैं। कई लोगों के पास एक से अधिक हथियार हैं।

हालांकि हथियार रखने का कारण आत्म सुरक्षा को बताया जाता है, पर सिरफिरे लोग तो उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि यह पूरी चुनावी प्रक्रिया शांति से संपन्न हो सकेगी। अमेरिका में 'गन कल्चर' पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। जब कोई ऐसी घटना होती है, तो यह बहस तेज हो जाती है। अभी कांग्रेस में हथियार रखने के बारे में नियम बनाने को लेकर प्रस्ताव भी विचाराधीन है, पर इस मुद्दे पर भी बड़ा विभाजन है। अमेरिका में विभाजन और हिंसा के संबंध में विचार करते हुए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वहां तरह-तरह की लॉबी सक्रिय हैं तथा उनका बड़ा प्रभाव है। 'गन लॉबी' भी बहुत ताकतवर है। ट्रंप भी इस लॉबी के बड़े समर्थक हैं। अब देखना है कि वे आगे क्या करते हैं।

जहां तक विदेश नीति का सवाल है, तो अगर बाइडेन फिर जीतते हैं, मौजूदा नीतियां ही जारी रहेंगी। अगर ट्रंप की वापसी होती है, तो वे रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। वे अपने बयानों में कहते भी रहे हैं कि वे चौबीस घंटे में इस युद्ध को रोक देंगे। रूस का मानना है कि यह लड़ाई यूक्रेन के साथ नहीं, बल्कि अमेरिका और नाटो के साथ है। हाल में नाटो की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो सम्मेलन हुआ है, उसमें यूक्रेन को मदद देते रहने की बात हुई है। भविष्य ही बतायेगा कि आगे क्या होता है। अमेरिका में इस्राइली लॉबी भी बहुत मजबूत है और ट्रंप पर भी उसका प्रभाव है। अगर ट्रंप की जीत होती है, तो इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हौसला और बढ़ेगा। यह संभव है कि गाजा में शांति के लिए ट्रंप कोशिश करें, पर वह समझौता ऐसा होगा, जो इस्राइल के पक्ष में होगा।

अमेरिकी राजनीति के मौजूदा दौर को हमें भारतीय नजरिये से दो तरह से देखना चाहिए। एक तो यह है कि जब भी वहां रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहे हैं, तो दोनों देशों के संबंध आम तौर पर अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से निकटता भी रही है। हमले के बाद जो संदेश भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया, उसमें भी उन्होंने उन्हें 'मेरे दोस्त' कहकर संबोधित किया है। उनके कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गये थे, टेक्सस में स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप भी आये थे और दोनों नेताओं ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। यह असाधारण घटना थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 'अबकी बार ट्रंप सरकार' का नारा भी दे दिया था। आज वैश्विक मंच पर और अमेरिकी विदेश नीति में भी भारत का रणनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे में किसी भी अमेरिकी प्रशासन के लिए भारत को अनदेखा करना असंभव है, पर वे दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

आज का इतिहास

1872 ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया। इससे पहले मतदान खुले तौर पर किए जाते थे।
1931 पहला वातानुकूलित पानी का जहाज 'मरिपोसा' शुरू हुआ।
1942 जर्मन इंजीनियरों के परीक्षण ने पहली बार जेटेंगेंगिन के साथ मेसर्शचिट मी 262 उड़ाया।
1944 ब्रिटिश सैनिकों ने नॉरमैंडी की बोर्केबस पर्वतीय श्रृंखला पर कब्जा किया।
1951 उरुग्वे ने संविधान स्वीकार किया।
1955 पहली बार परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से बेचा गया।
1968 अर्धचालक कंपनी इंटेल की स्थापना की गयी।
1969 मैसाचुसेट्स में चैप्पाक्विडिक द्वीप पर एक पार्टी के बाद, यूनाइटेडस्टेट्स सीनेटर टेड कैनेडी ने अपनी कार को एक लकड़ी के पुल से निकाल दिया।
1977 वियतनाम संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।
1984 एक बंदूकधारी ने कैलिफ़ोर्निया के सैन डिएगो के सैन ग्सिड्रो अनुभाग में मैकडोनाल्ड के रेस्तरां में 21 लोगों की हत्या कर दी और 15 अन्य को घायल कर दिया।
1984 बेवर्ली बर्न्स दुनिया की पहली महिला बोइंग 747 कप्तान बनी।
1994 ब्यूनस आयर्स के एक यहूदी धर्म केंद्र में बम फटने से पैंसठ लोगों की मौत हो गई, जिससे यह अर्जेंटीना का अब तक का सबसे घातक केंद्र है।
1995 सुस्ती के एक लंबे समय के बाद, सौतेरेय हिल्स ज्वालामुखी फिर भी एक चल रहा है, जो मोंटसेराट द्वीप को नष्ट कर रहा है।
1995 सेलेना का एल्बम ड्रीमिंग ऑफ यू, तेजो संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1999 128 वाँ ब्रिटिश गोल्फ ओपन : कैमावेसी स्कॉट में।
2000 एलेक्स साल्मॉन्ट ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दिया।
2010 यू.के. अफगानिस्तान में 40% वृद्धि सहित गरीब देशों को सहायता बढ़ाएगा, जबकि रूस, चीन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे पॉवरहाउस को सहायता कम करेगा।
2011 अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं की कमान अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रायस से अमेरिकी मरीन कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जेनरल जॉन आर. एलन को स्थानांतरित हो गई।
2011 फीनिक्स, एरिजोना एक धूल भरी आंधी से मारा जाता है, जिसे हाबोब भी कहा जाता है।
2012 किंग जोंग-इल के बेटे किंग जोंग-उन को उत्तर कोरिया का आधिकारिक सर्वोच्च नेता घोषित किया गया है; वह अब कोरियाई पीपुल्स आर्मी में मार्शल की रैंक भी रखता है।

जम्मू-कश्मीर में फिर से सिर उठा रहे आतंकियों को केंद्र ने दिया कानूनी संदेश

कमलेश पांडे

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आतंकी जिस तरह से पुनः सिर उठाते दिखाई पड़े, उसके मुताल्लिक केंद्र सरकार ने बिल्कुल सटीक उपाय किये और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जैसी शक्तियों से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को भी लैस कर दिया। इससे साफ है कि जम्मू-कश्मीर में फिर से सिर उठा रहे आतंकियों को केंद्र सरकार ने सख्त कानूनी संदेश दिया है कि चाहे जितना उधम मचा लो, पर कानून के शिकंजे से बच नहीं पाओगे।केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव बाद भी तुम्हारे पॉलिटिकल बॉस किसी काम नहीं आएंगे! लिहाजा, इसके सियासी और प्रशासनिक दोनों मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों को तो मानो मिर्ची लग चुकी है।

ऐसे में यह समझ में नहीं आता कि जब इसी साल सितंबर के अंत तक वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो फिर आतंकी वारदातें एकाएक बढ़ क्यों गईं? घाटी तो छोड़िए जम्मू में आतंकियों को स्थानीय समर्थन कैसे संभव हो गया, जैसा कि पुलिस खुलासा कर चुकी है? ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकी वारदातों के पीछे कहीं न कहीं किसी सफेदपोश नेता और उनके शातिर कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका होगी ही! बस, इस नजरिए से पुलिस जांच तेज करने की जरूरत है। जैसे अभी स्लीपर सेल वाले पकड़े जा रहे हैं, उसी तरह से ये सफेदपोश भी नहीं बचेंगे।

कहना न होगा कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर की धरती सैनिकों और आम आदमी के खून से लाल की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में देशद्रोही ताकतों की शिनाख्त और सख्त सजा दोनों की दरकार है। उम्मीद है कि उपराज्यपाल की बढ़ी शक्तियों से आतंकियों के नापाक मंसूबों को चकनाचूर किया जा सकेगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) जैसी शक्तियां बढ़ाने वाली धाराएं जोड़ी हैं, जिसके बाद तबादले-पोस्टिंग में अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी जरूरी हो चुकी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तैनाती व तबादले एलजी की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेंगे। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 जुलाई 2024 शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की, जिसमें एलजी को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

वहीं, उपराज्यपाल भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से जुड़े मामलों के अलावा महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति पर भी फैसले कर सकेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय ने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम में इन प्रावधानों का जिक्र पहले से ही है। फिलवक्त रोजमर्रा के कामकाज में और स्पष्टता के लिए नियमों में

कुछ बदलाव किए गए हैं। पुनर्गठन अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

केंद्र के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य में सरकार किसी की बने, अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेंगी। हालांकि, केंद्र के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में भी दिल्ली जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जहां सरकार और एलजी के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। बहरहाल राज्य में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिन्हा एलजी हैं। इसलिए उनसे टकराव की नौबत कम ही आएगी।

उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019) संसद में पारित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। जम्मू-कश्मीर जून 2018 से केंद्र सरकार के अधीन है। 28 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय ने प्रशासन के नियमों को नोटिफाई किया था, जिसमें उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के कामकाज की स्पष्ट व्याख्या की हुई है।

वहीं, अब संशोधित नियमों में अहम बिंदु जोड़े गए, जिसके मुताबिक, पहला, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तबतक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता, जबतक मुख्य सचिव के जरिए उसे राज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है।

दूसरा, किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या न देने और अपील दायर करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखना जरूरी होगा। दूसरे शब्दों में, अभियोजन मंजूरी प्रदान करने या अपील दायर करने के लिए भी एलजी की मंजूरी लेनी होगी।

तीसरा, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के जरिए उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पेश करेगा।

चतुर्थ, कारागार, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बंधित मामले मुख्य सचिव के माध्यम से गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव की ओर से एलजी के समक्ष पेश किए जाएंगे।

पंचम, प्रशासनिक सचिवों की तैनाती, तबादले तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बंधित मामलों में प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव की ओर से एलजी के पास भेजे जाएंगे।

बता दें कि दिल्ली के केंद्र शासित राज्य होने के नाते वहां एलजी को ही सरकार माना जाता है। क्योंकि दिल्ली में कोई भी अधिसूचना बगैर एलजी की मंजूरी के जारी नहीं हो सकती। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद उपराज्यपाल के पास सर्विसेज विभाग, जमीन और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग की जिम्मेदारी एलजी के पास है। सरकार अधिकारी को हटाना या लगाना चाहती है तो उसे उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सीधे एलजी की होती है। पुलिस सीधे उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है।

बहरहाल, जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस अधिसूचना को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। अधिसूचना के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद भी एलजी की भूमिका ताकतवर बनी रहेगी। हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बना देना चाहिए। उधर, कांग्रेस ने भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

वहीं, नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की बात में दम है कि अब तो हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक है। इसलिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टाम्प, मुख्यमंत्री से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए नए परिवर्तन से हम असहमत हैं।

वहीं, पीडीपी की चिंता स्वाभाविक है कि यह आदेश जम्मू-कश्मीर में अगली निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास है। उधर, अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने ठीक ही कहा है कि इस नए फैसले का उद्देश्य राज्य को खोखला बनाना है, जिसमें निर्वाचित सरकार के लिए कोई शक्ति नहीं बचेगी। सवाल है कि जब नेता लोग आतंकियों से सहानुभूति रखेंगे, पाकिस्तान के तलवे सहलाने वाली बातें बोलेंगे, तो फिर केंद्र उनकी नकेल कसने के यत्न करेगा ही। सच कहूं तो जम्मू-कश्मीर के जो वर्तमान हालात हैं, उसके मद्देनजर केंद्र के नए फैसले से असहमत होने का कोई कारण भी नहीं है। इसलिए शांति चाहते हो तो सुधर जाओ, अन्यथा केंद्र के इशारे पर कुचले जाओगे, सर्प फन मानिंद!

ट्रम्प पर हमले से अमरीकी समाज में बढ़ सकता है तनाव

हर्ष वर्द्धन शांगला

राष्ट्रपति पद के संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प पर सप्ताहांत में की गई हत्या की नाकाम कोशिश 2024 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में बड़ा बदलाव ला सकती है। घायल कान, चेहरे पर बहता हुआ खून लेकिन दृढ़ निश्चयी और लडने के जज्बे वाले ट्रम्प की तस्वीर (मुट्ठी बांधकर हवा में मुक्का मारते हुए) आने वाले कुछ समय के लिए अमरीकी राजनीति की परिभाषित छवि बनने की उम्मीद है। यह मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की छवि के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है, जिन्हें अपनी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर अनिश्चितताओं के कारण राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के लिए लगातार जोरदार आवाजों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हत्या की कोशिश की 'कड़ी निंदा' करने वाले पहले लोगों में से थे। ''मेरे मित्र, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमरीकी लोगों के साथ हैं।'' पी.एम. ने एक्स पर पोस्ट किया। अमरीका में, रिपब्लिकन और डैमोक्रेट दोनों ने हमले की डक्षनदा की है। घटना के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रम्प से बात की। राष्ट्रपति ने कहा ''अमरीका में इस तरह की डक्षहसा के लिए कोई जगह नहीं है... यह बीमार करने वाली बात है।'' बाइडेन के हवाले से कहा गया है, ''यही एक कारण है कि हमें इस देश को एकजुट करना है। आप ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकते। हम ऐसे नहीं हो सकते। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।'' पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और बराक ओबामा ने भी ट्रम्प की जान लेने की कोशिश को अस्वीकार किया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों की ओर से हमले की डक्षनदा अमरीकी राजनीति में मतभेद को दूर करेगी या नहीं। वास्तव में, ध्रुवीकरण इतना मजबूत है कि हमला अमरीकी समाज में तनाव को बढ़ा सकता है। हमला किस वजह से हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह ट्रम्प द्वारा खुद को उन डैमोक्रेट्स का शिकार बताए जाने की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिनका घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ट्रम्प को नवंबर के चुनावों में किसी भी कीमत पर जीतने से रोका जाए। ट्रम्प ने खुद भी डैमोक्रेट्स पर उन्हें फर्जी मामलों और आरोपों में फंसाने का आरोप लगाने का कोई मौका नहीं गंवाया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति पद हासिल करने के उनके अवसरों को बाधित करना था। इसलिए, ट्रम्प को सहानुभूति वोट मिलना तय है। अगर पेंसिल्वेनिया की भीड़ के उद्घोष को कुछ भी कहा जाए, तो उनके समर्थक और अन्य लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। वह उन अनिश्चित मतदाताओं के वोट भी जीत सकते हैं, जो ट्रम्प के विरोध में अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। विडंबना यह है कि हत्या की कोशिश राष्ट्रीय और मीडिया की नजरों को बाइडेन से हटाकर सीधे ट्रम्प पर डाल देती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बाइडेन ट्रम्प के प्रतिद्वंद्वी के रूप में बने रहेंगे, जिससे रिपब्लिकन्स के लिए व्हाइट हाऊस हासिल करने की पूर्व राष्ट्रपति की संभावनाएं बढ़ेंगी।

राजनीति में प्रतिस्पर्धी मानें, दुश्मन नहीं

अवधेश कुमार

13 जुलाई का दिन अमेरिका ही नहीं विश्व इतिहास के लिए अत्यंत भयावह और सबक लेने वाले दिन के रूप में दर्ज हो गया है। अमेरिका जैसे पुराने लोकतांत्रिक देश में रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प पर सार्वजनिक सभा में गोली चलाकर हत्या का प्रयास अचंभित करने वाली घटना है। पेनसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी रैली कर रहे थे। अचानक से गोली आई और ट्रम्प के कान को छूते हुए निकल गई।

हालांकि अमेरिकी इतिहास में इसके पूर्व दो बार राष्ट्रपति उम्मीदवारों पर हमले के रिकॉर्ड हैं। 1912 में राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे तब मिल्वौकी में एक भाषण के लिए जाते समय एक सैलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी. वे बच गए थे। गोलीबारी के बावजूद उन्होंने भाषण दिया। 1972 में अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस को तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान वाशिंगटन डीसी के बाहर गोली मार दी गई थी।

हमले के कारण उनकी कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। लेकिन वर्तमान हमले के कारण, परिस्थितियां और इसके पीछे की विचारधारा अलग है। अमेरिका का संघीय जांच ब्यूरो और अन्य एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं और हत्या के प्रयास के कारणों का पता आने वाले समय में चलेगा। जांच रिपोर्ट जो भी कहे, आम अमेरिकी और इस समय अमेरिका सहित विश्वभर में राजनीति, एक्टिविज्म और नैरेटिव की प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखने वाले समझ सकते हैं कि इसके कारण क्या होंगे।

डोनाल्ड ट्रम्प पर हमले की सूचना आते ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसकी निंदा करते हुए अमेरिकी समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान न होने का बयान दिया तथा अपील की कि हमें सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी टेलीविजन प्रसारण में इसकी

निंदा करते हुए यही कहा। समाचार के अनुसार बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रम्प से फोन पर बातचीत भी की।

किंतु सच यह भी है कि डेमोक्रेटिक सहित अमेरिका के बुद्धिजीवियों, मीडिया, एक्टिविस्ट, यहां तक कि प्रशासन के एक बहुत बड़े वर्ग ने डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी विचारधारा के सामान्य विरोध की जगह उसके प्रति जिस ढंग से घृणा पैदा किया है, उसका असर अमेरिकी समाज पर है. ट्रम्प को डेमोनाइज करते हुए उन्हें हिटलर से लेकर न जाने क्या-क्या उपाधि दी गई है।

उन्हें लोकतंत्र ही नहीं, अमेरिकी समाज और एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया है। अमेरिका में ऐसे निहित स्वार्थी समुदाय हैं जिनके अंदर यह भाव गहरा हुआ है कि अगर ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बने तो उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को लगता है कि उन्हें देश से जाना पड़ सकता है या फिर उन्हें यहां कैंपों और जेलों में रहने को विवश होना पड़ सकता है। संयोग देखिए कि ट्रम्प पर गोली उस समय चली जब वह एक चार्ट पढ़ते हुए बता रहे थे कि अमेरिकी सीमा पार करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है।

ट्रम्प एवं उनके समर्थकों ने अमेरिका में अवैध रूप से आने और रहने को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसका व्यापक समर्थन भी है। यह अनायास नहीं है कि ट्रम्प को किसी तरह राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर करने के हर प्रयास अमेरिका में हुए हैं, हो रहे हैं। न्यायालय द्वारा उन्हें सजा दिलाकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से वंचित करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। चूंकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है इसलिए संभव है कुछ व्यक्तियों या समूहों ने उन्हें रास्ते से ही हटा देने का निर्णय किया हो। इसलिए यह हमला अंतिम नहीं हो सकता।

आप देखेंगे कि इस समय विश्व भर में इस तरह की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से उभरी है। पूर्व में क्रांति कर सत्ता बदलने के विचार-व्यवहार वाले कम्युनिस्टों की जगह एक ऐसी नव वाममार्गी विचारधारा पूरी दुनिया में दिख रही है जो राष्ट्रवाद, रिलीजन, मजहब और अपने देश की सभ्यता संस्कृति पर गर्व करने वाले संगठनों को लेकर घृणा-विरोध नैरेटिव और अन्य संसाधनों से पैदा कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नाम या नेताओं की पृष्ठभूमि पर मत जाइए, आपको अलग-अलग देशों में ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देंगी और उनके परिणाम भी सामने आए हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या की कोशिश हम सबके लिए सबक होना चाहिए। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में असहमति और मतभेद होना, विचारधाराओं पर एक-दूसरे से संघर्ष भी स्वाभाविक है। किंतु राजनीति और सार्वजनिक जीवन में घृणा और दुश्मनी का कोई स्थान नहीं। हम एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी होंगे, राजनीतिक और वैचारिक विरोधी होंगे किंतु दुश्मन नहीं, जिसके विरुद्ध इतनी घृणा पैदा की जाए कि लोग हिंसा की सीमा तक पहुंच जाएं। यह सभी पक्षों पर लागू होता है।

हालांकि जैसा वातावरण अमेरिका सहित कई देशों में बन चुका है उसमें कोई तत्काल इससे सबक लेगा, इसकी संभावना कम है। अगर सबक लेकर हम संभालने या संभालने की कोशिश करें तो उसमें भी सफलता की संभावना कमजोर हो गई है क्योंकि वातावरण काफी विषाक्त बन चुका है इसलिए सबके सामने यही प्रश्न है कि स्थिति को हम कैसे संभालें।

राजस्थान भाजपा में अभी से उठने लगे बगावत के स्वर

रमेश सर्राफ धमोरा

लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा में जमकर उठा पटक मची हुई है जो भविष्य में आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सरकारी गाड़ी व अन्य सरकारी सुविधाएं भी लौटा दी है। यहां तक की डा. किरोड़ी लाल मीणा बजट सत्र में भी विधानसभा में नहीं आने की घोषणा कर चुके हैं। डा. किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। सरकार में हो या विपक्ष में वह अपनी बात पूरी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं।

डॉ. किरोडी लाल मीणा मंत्रिमंडल के गठन के वक्त से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुरूप महत्व नहीं मिला था। जिसके चलते वह अंदर खाने नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। डॉ. किरोडी लाल मीणा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके उपरांत भी उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। कहने को तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज नहीं है और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बजट सत्र में भी विधानसभा नहीं आकर डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी खुलकर जता दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने उपेक्षा से पहले से ही दुखी है। गाहे बेगाहे अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती है। विधानसभा में भी वसुंधरा समर्थक विधायक सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को पूरी आशा थी कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर जिस प्रकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेब से पर्ची निकाल कर वसुंधरा राजे से नए मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा करवाई। उससे वसुंधरा राजे की आम जनता में काफी

फजीयत हुई थी। जिसे वसुंधरा अभी तक भूल नहीं पाई है।

लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार से जहां केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है वही राजस्थान में तो भाजपा सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य सभी अग्रिम पंक्ति के नेताओं की जमकर किरकिरी हुई है। केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोक सभा सीट से महज 55711 वोटो के अंतर से जीत सके हैं।

इसी तरह तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस के अनजान से प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा को 115677 वोटो से हराया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को 274440 वोटो से व 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच को 303464 वोटो से चुनाव हराया था।

लोकसभा चुनाव में चूरू सीट पर भाजपा सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटे जाने से जाटों में भाजपा के प्रति काफी नाराजगी व्याप्त हो गई थी। जिसका खामियाजा उन्हें जाट बहुल अधिकांश सीटों पर हार कर चुकाना पड़ा था। पिछली बार भाजपा के पांच सांसद जाट वर्ग से थे। जबकि अबकी बार अजमेर से भागीरथ चौधरी जीत पाए हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने पुत्र के झालावाड़ संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रही थी। उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में तो शामिल किया गया था। मगर चुनाव प्रचार के लिए कहीं नहीं भेजा गया।

झुंझुनू से भाजपा टिकट पर चुनाव में पराजित हुए शुभकरण चौधरी ने अपनी हार का कारण अग्निवीर योजना को बताया था। भाजपा के बहुत से नेताओं का मानना है कि राजस्थान से सेना में सर्वाधिक नवयुवक भर्ती होते हैं। अग्निवीर योजना आने के बाद राजस्थान के युवाओं में खासी नाराजगी व्याप्त हो रही है। कांग्रेस ने वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना बंद कर देगी। इससे बड़ी संख्या में नवयुवकों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी सभी 25 संसदीय सीटों पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके थे। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव के दौरान व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर सके। इसी के चलते अपने गृह जिले भरतपुर की लोकसभा सीट भी हार गए।

राजस्थान में भाजपा की सरकार बने सात महीने से अधिक का समय हो चुका है। मगर अभी भी सरकार पर मंत्रियों की पकड़ नहीं बन पाई है। अधिकारी वर्ग मंत्रियों की बातों को अधिक तवज्जो नहीं देते हैं। जिसके चलते मंत्रियों द्वारा आम जनता मे की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने से उनकी स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष एक ही जाती के हैं। विभिन्न निगम, बोर्ड, आयोग, मण्डलों में भी अभी तक या तो पीटे हुए मोहरों को या अधिकारियों को ही नियुक्ति दी गई है। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल पाई है।

अगले कुछ महीनो में प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पांच में से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन यदि भाजपा इन पांच सीटों को फिर से हार जाती है तो मुख्यमंत्री की नकारात्मक छवि बनेगी। इसलिए सरकार के समक्ष सभी पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीतना एक मजबूत चुनौती बन गई है। भाजपा यदि पांचों सीटों पर उपचुनाव में जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव की हार का गम कुछ कम होगा। वरना आने वाले समय में पार्टी आलाकमान द्वारा राजस्थान को लेकर कई बड़े निर्णय किए जाने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है।

असली केदारनाथ धाम बनाम नकली केदारनाथ धाम

अभिनय आकाश

उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है ये तो आप सभी को पता है। अब ठीक वैसा ही केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाने की तैयारी हो रही है। केदारनाथ का डुप्लीकेट बनाए जाने से साधु-संत और शंकराचार्य नाराज है। अब तो आंदोलन की धमकी तक दी जाने लगी है। ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा है भगवान भोलेनाथ का पवित्र केदारनाथ धाम। ये भव्य मंदिर उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग में है। केदारनाथ से मिलता-जुलता मंदिर देश की राजधानी दिल्ली में भी बनाने की तैयारी हो रही है। मंदिर का मॉडल देखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। मंदिर का डिजाइन और रंग भी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के तरह का ही होगा। मजे की बात ये है कि इस मंदिर का नाम भी केदारनाथ धाम रखने का प्रस्ताव है। इसे दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बनाया जा रहा है। डुप्लीकेट केदारनाथ धाम का भूमि पूजन भी हो चुका है। 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, कई सांसद और साधु संतों की मौजूदगी में बुराड़ी स्थित मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोग और व्यपारी दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाने के विरोध में हैं। ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जब केदारनाथ में इस तरह की नारेबाजी देखने को मिली है। केदारनाथ के पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में केदारनाथ धाम का निर्माण नहीं रूका तो पूरी केदारघाटी में आंदोलन होगा। दिल्ली में केदारनाथ जैसा मंदिर बनाए जाने पर शंकराचार्य भी गुस्से में है। दिल्ली में भूमि पूजन में शामिल होने के बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निशाने पर हैं। अब उन्होंने सफाई दी है कि केदारनाथ जैसा मंदिर बनने से केदारनाथ धाम की आस्था कम नहीं होगी। जो केदारनाथ अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं, ऊंचे पर्वतों से गूंजती मंदिर की घंटियों के लिए जाना जाता था। इन दिनों वहीं से विरोध प्रदर्शन की आवाज आ रही है। इस विरोध में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुरोहित और पुजारी भी शामिल हैं। अभी ये शोर थमा भी नहीं था कि ज्योति मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी नाराजगी सामने आ गई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाला का आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा है। केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण होगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है। कोई जांच शुरू नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? शंकराचार्य जिस सोना घोटाले का जिक्र कर रहे हैं वो मामला जून 2023 में चर्चा में आया था। दिल्ली के बुराड़ी में तीन एकड़ में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए बकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में पहले से केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलते जुलते मंदिर बने हुए हैं। इंदौर में केदारनाथ से मिलता जुलता पंडाल बनाया गया था। लेकिन वो अस्थाई था। वहीं मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर बनाया गया है। लेकिन ये पंडाल नहीं बल्कि एक मंदिर है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में जब पहले से ही केदारनाथ-बद्रीनाथ मंदिर जैसे मिलते जुलते मंदिर है तो दिल्ली वाले मंदिर को लेकर आपत्ति क्यों है? ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का कहना है कि दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ मंदिर एक मंदिर है, कोई धाम नहीं है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे अनुरोध पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए। मंदिर ट्रस्टियों के सहयोग से बनाया गया है और उनमें से कई उत्तराखंड के हैं।

जर्मनी में विदेशी छात्रों को मिलती है कम कीमत में क्वालिटी एजुकेशन

दुनिया भर से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के लिए जर्मनी एक खुली और रंगबिरंगी सोसायटी है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जर्मनी पहले ही हॉट स्पॉट बन चुका है और इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़कर 3.60 लाख पहुंच चुकी है यानी प्रत्येक सेमेस्टर में एक चौथाई छात्र विदेशी हैं।

दुनिया भर से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के लिए जर्मनी एक खुली और रंगबिरंगी सोसायटी है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जर्मनी पहले ही हॉट स्पॉट बन चुका है और इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़कर 3.60 लाख पहुंच चुकी है यानी प्रत्येक सेमेस्टर में एक चौथाई छात्र विदेशी हैं।

जर्मनी में क्यों करें पढ़ाई

जर्मनी में पढ़ाई करने के कई कारण हैं जिसमें प्रमुख है शिक्षा की बेहतरीन गुणवत्ता, ट्यूशन फीस में छूट, शानदार करियर के मौके, इंगलिश में पढ़ाए जाने वाले इंटरनैशनल डिग्री प्रोग्राम आदि शामिल हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटिज की दुनिया में काफी प्रतिष्ठा है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जर्मनी की 47 यूनिवर्सिटिज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटिज में शामिल हैं। आप इस बात पर विश्वास करें या नहीं लेकिन यह सच है कि जर्मनी की कई यूनिवर्सिटिज ट्यूशन फीस नहीं लेती हैं और यह बात विदेशी छात्रों पर भी लागू होती है। इसके अलावा यहां छात्रों के पास स्कॉलरशिप प्राप्त करने के भी कई मौके होते हैं खासतौर से जर्न अकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के जरिए। इसके भारत में कई ऑफिस हैं जो भारतीय छात्रों को उनकी जरुरत के हिसाब से कोर्स मुहैया कराती है।

भाषा

जर्मनी में विदेशी छात्र करीब 2 हजार ऐसे कोर्सेस में से अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है। इसलिए यहां जर्मन भाषा की समझ जरूरी नहीं है। हालांकि जर्मन भाषा को सीखना आगे आपके ही काम आएगा।

आइडिया का देश

जर्मनी शुरू से ही अविष्कारों का देश रहा है यहां प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ऑटोमोबाइल और एमपी 3 फॉर्मेट का अविष्कार हुआ है। अभी तक करीब 80 जर्मन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी सबसे इनोवेटिव देश है। इसमें जर्मनी की यूनिवर्सिटिज अहम रोल निभाती है क्योंकि यहां रिसर्च काफी मजबूत है।

किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र 18 महीने जर्मनी मे नौकरी ढूंढने के लिए रूक सकते हैं। जर्मनी इंडस्ट्रीयल इनोवेशन और मैनुफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है इसलिए यहां हर समय इंजिनियर्स की कमी रहती है। इसके अलावा यहां कई ऐसे शहर हैं जहां होली और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसके कारण यह भारतीयों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है।

ये 5 वॉटर कोर्स दिलाएंगे विदेश जाने का मौका

पानी की कमी और खराब गुणवत्ता जैसी समस्याएं आज पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये समस्याएं किसी एक देश की सीमाओं में नहीं सिमटी हैं। ऐसे में वैश्विक जल प्रबंधन के मुद्दों को सुलझाने के लिए कुशल रणनीतिकारों और विकास विशेषज्ञों की ज़रूरत है। दुनिया भर में कई देश अपने जल संसाधनों का प्रबंधन टिकाऊ तरीके से करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास सही विशेषज्ञता और व्यावहारिक ज्ञान दोनों का मिश्रण हो।

क्रॉस कल्चरल कम्यूनिकेशन स्किल

वैश्विक स्तर पर टिकाऊ जल कूटनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना और वैश्विक भाषाई परिवेश में काम करना सीखना है। पेशेवर कूटनीतिज्ञों को कूटनीतिक वार्ता, हितधारकों को जोड़ने और नीतिगत पैरवी करते समय सावधानी और खुले दिमाग का परिचय देना चाहिए।

तकनीकी विशेषज्ञता

जल विज्ञान, जल प्रबंधन सिद्धांतों और पर्यावरण विज्ञान में मजबूत आधार होना इस पेशे की नींव है। जल मॉडलिंग, जीआईएस और डेटा विश्लेषण में विशेषज्ञता आमतौर पर हायर करने वाले ढूंढते हैं।

नीति विश्लेषण और विकास

जल क्षेत्र का मूल जल नीतियों का विश्लेषण करना, उनके लागू करने के परिणामों का अध्ययन करना और बेहतर, टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के विकास में शामिल होना है।

वार्ता और समाधान

जल पेशेवरों में कूटनीतिक स्किल मजबूत होनी चाहिए और उन्हें विवादों का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि पानी तनाव और संघर्ष का कारण न बने।

कोर्सेज एंड ट्रेनिंग, वाटर डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस

अंतर्राष्ट्रीय जल कानून, सीमा पार जल प्रबंधन और कूटनीति पर बल देने वाले पाठ्यक्रम छात्रों को साझा जल संसाधनों के प्रबंधन में शामिल जटिल मुद्दों की बुनियादी समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

पर्यावरण नीति और रेगुलेशन

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ जल संसाधनों के लिए नियामक व्यवस्थाओं की जानकारी होना उचित कानून और रणनीतियां बनाने के लिए ज़रूरी है।

अगर आप विदेश जाकर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी आर्टिकल है। यहां पर हम यहां पर टॉप-5 वॉटर डिप्लोमैसी और डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आप बेहतरी करियर बना सकते हैं। साथ ही लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई भी कर सकते हैं।

पारियोजना प्रबंधन

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने के लिए नेतृत्व क्षमता, बजट बनाने का कौशल, सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली टीम वर्क की आवश्यकता होती है।

जल विज्ञान और जल प्रबंधन

ऐसे तकनीकी पाठ्यक्रम मौजूद हैं जो जल विज्ञान मॉडलिंग, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन जैसे विषयों पर पढ़ाते हैं। ये पाठ्यक्रम जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

अंतर-सांस्कृतिक संचार और वार्ता

इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर-सांस्कृतिक संचार और वार्ता कौशल पर केंद्रित होते हैं, जो वैश्विक जल क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

पेशेवर विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसे संगठन अक्सर जल संसाधन प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए पेशेवर विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं।

ये हैं देश की सबसे महंगी डिग्रियां, जानिए एवरेज फीस

समय के साथ देश में शिक्षा भी महंगी हो गई है। शायद यही वजह है कि अब कुछ डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, सरकारी कॉलेजों में फीस फिर भी कम है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों कई कोर्सेज के फीस बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं देश की सबसे महंगी डिग्रियों के बारे में

भारत में मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित कई कोर्स संचालित किए जाते हैं। कई कोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद बढ़िया सैलरी भी मिलती है। हालांकि, ये डिग्रीयां महंगी भी होती हैं। ऐसे में आइए हम आपको बता दें कि देश की सबसे महंगी डिग्रियों के बारे में?

मेडिसिन

मेडिसिन की डिग्री भारत में महंगी डिग्री में एक है। मेडिसिन की पढ़ाई सरकारी कॉलेजों में सस्ती होती है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो मेडिसिन की डिग्री के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है।

इंजीनियरिंग डिग्री

भारत में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए सरकारी स्कूलों में फीस एक वर्ष की 2 लाख रुपये तक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए 10 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा तक की फीस एक वर्ष के लिए देना पड़ सकता है।

बिजनेस डिग्री

बिजनेस मैनेजमेंट सहित अन्य कोर्सेज के लिए आईआईएम सहित अन्य सरकारी कॉलेजों को छोड़कर स्टूडेंट्स 20 से 25 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को कई तरह की स्कॉलरशिप भी दी जाती है।

लॉ कोर्सेज

लॉग की डिग्री लेने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट्स को कुल 10 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बदलते दौर के साथ लॉ के क्षेत्र में करियर ऑप्शन भी बढ़ गए हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में हर वर्ष स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई करते हैं। यही वजह है कि कई प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से फीस भी बढ़ा दी गई है।

एविएशन

एविएशन की डिग्री भी देश की महंगी डिग्रियों में एक है। एविएशन की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपये से 15-20 लाख रुपये की फीस एक वर्ष की देनी पड़ सकती हैं। हालांकि, एविएशन की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को बढ़िया सैलरी भी मिलती हैं।

डिजाइन

डिजाइन कोर्सेज की गिनती भी महंगी डिग्रियों में होती है। देश के कई संस्थानों से डिजाइन कोर्सेज को करने के लिए स्टूडेंट्स को 10 से लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि, डिजाइन कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को बढ़िया सैलरी भी मिलती है।

फूड स्टार्टअप्स में ऐसे बनाएं करियर

बदलते जमाने के साथ लोग परंपरागत कोर्सेज से हटकर कुछ ऐसे नए कोर्स कर रहे हैं, जिससे वे न सिर्फ पैसा कमा कर रहे हैं, बल्कि अपना सपना भी पूरा कर रहे हैं। इन्हीं फील्ड में फूड स्टार्टअप भी नया विकल्प बनकर उभरा है। जिसमें आप बेहतर करियर बना सकते हैं।

खाने की दुनिया लगातार बदल रही है और इस बदलाव में सबसे आगे चल रहे हैं फूड आंत्रप्रेन्योर्स। ये नई पीढ़ी के बिजनेस करने वाले लोग परंपरागत रेस्टोरेंट के तरीकों को तोड़ रहे हैं। ये ना सिर्फ खाने के बारे में हमारे नजरिए को बदल रहे हैं, बल्कि खाने से जुड़े स्टार्टअप्स में रोजगार के नए मौके भी पैदा कर रहे हैं। अगर आप भी इस रोमांचक फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फूड बिजनेस से जुड़े कौन-कौन से कोर्स हैं, करियर के कौन से विकल्प मौजूद हैं और आपको किन खासियतों की ज़रूरत होगी।

पाठ्यक्रम और शिक्षा

अच्छा खाना पकाने की शिक्षा के बिना ज्यादातर फूड एंटरप्रेन्योर्स अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। वैसे तो कुकिंग स्कूल क्लासिकल और प्रैक्टिकल तरीके से खाना बनाना सिखाने के साथ-साथ किचन मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, लेकिन फूड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बिजनेस चलाने के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इन कार्यक्रमों में खासतौर पर फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में जानकारी दी जाती है। इससे भविष्य के फूड एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी स्किल्स हासिल हो जाते हैं।

फूड स्टार्टअप्स में करियर विकल्प

शेफप्रेन्योर

जो लोग खाने के क्षेत्र में नयापन लाना चाहते हैं, उनके लिए शेफप्रेन्योर बनना एक बेहतरीन विकल्प है। ये क्रिएटिव फूड प्रोडक्ट डेवलपर होते हैं, जो अपने पाक कला के हुनर से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनका स्वाद ग्राहकों के ज़हन में बस जाता है और उनकी ब्रांड प्रतियोगिता में अलग पहचान बनाती है।

फूड टेक्नोलॉजिस्ट

फूड टेक्नोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो खाने के सामान बनाने और उनकी खासियतों को बनाए रखने में माहिर होते हैं। फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुरक्षा और शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करते हैं, साथ ही नए प्रोडक्ट बनाने और मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के अवसर तलाशते हैं।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट

फूड स्टार्टअप बाजार में सफलता के लिए अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सोशल मीडिया, इनफ्लुएंसर कोलैबोरेशन और एक्सपीरियंसल मार्केटिंग कैम्पेन्स जैसे अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रांड रिकॉल, लॉयल्टी और डिमांड पैदा करने के लिए अपने क्रिएटिव स्किल्स और रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हैं।

सप्लाई चेन और ऑपरेशन्स मैनेजर

फूड स्टार्टअप की सफलता के लिए किसी भी काम की तरह सप्लाई चेन का सुचारू रूप से चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सप्लाई चेन और ऑपरेशन्स मैनेजर सामान मंगवाने, प्रोडक्शन प्रोसेस को लागू करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट का समन्वय करते हैं, जिससे पूरी सप्लाई चेन एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से चलती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

छगन भुजबल से मुलाकात पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल और एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलों का दौर लगातार जारी है। इस सब के बीच शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने बारामती में कुछ अच्छे भाषण दिये थे और मेरे बारे में कुछ कहा था। फिर वो मुझसे मिलने आये। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी... मैं उठा और उनसे मिला। उन्होंने मुझे महाराष्ट्र के हित के लिए बातें बताईं और चाहते थे कि मैं चर्चा के लिए आऊं। उन्होंने मुझे एक बैठक के बारे में बताया जिसमें मैं शामिल नहीं हुआ। वह बैठक सीएम ने बुलाई थी, वह आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक थी। शरद पवार ने यह भी बताया कि भुजबल ने मुझसे कहा कि कुछ कदम उठाएं अन्यथा महाराष्ट्र में कुछ समस्याएं होंगी...लेकिन मुझे लगता है कि समन्वय बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी फैसले हमें किनारे रखकर सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

नीति आयोग में फेरबदल पर प्रियंका का एनडीए पर कटाक्ष

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल के फेरबदल में नीति आयोग में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट से किसी भी नेता को नियुक्त नहीं करने को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वह नीति आयोग को अनैतिक सत्ता हथियाने करार देते हुए सीएम एकनाथ शिंदे की सेना से नेताओं के बहिष्कार को समझ सकती हैं। राज्यसभा सांसद ने नीति में फेरबदल पर एक समाचार पत्र के आर्टिकल को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुनर्गठित नीति आयोग में शिंदे सेना के लिए कोई जगह नहीं। जब नीति केवल अनैतिक रूप से सत्ता हथियाना है, तो बहिष्कार को समझा जा सकता है। एनडीए सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी ने सीबीआई को घेरा

नईदिल्ली। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को बाद में की गई गिरफ्तारी बताया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका के पक्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील देते हुए सिंघवी ने दावा किया कि एजेंसी के पास गिरफ्तारी के लिए न तो कोई सामग्री है और न ही आधार। सिंघवी ने आज दावा किया कि निचली अदालत द्वारा उन्हें ईडी के मामले में जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई ने जून 2024 तक उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने पर विचार नहीं किया था। सीबीआई ने जून तक मुझसे पूछताछ के बारे में नहीं सोचा है। घोटाला कथित तौर पर अगस्त 2022 में हुआ और आप जून में हैं। अगस्त से सिर्फ 2 महीने पहले, आपको अचानक उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस हुई? सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

योगी मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव

लखनऊ। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में बदलाव होने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन संगठन और मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव के बाद फेरबदल किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी उठापटक को लेकर भाजपा पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश ने कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उप्र में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है।

प. बंगाल में लाखों हिंदू नहीं दे पाए थे वोट : भाजपा

कोलकाता। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को पश्चिम बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी केवल 12 सीटों पर सिमट गई थी जबकि उसके नेता दावा कर रहे थे कि इस बार वे प. बंगाल में कम से कम 30 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। भाजपा का आरोप है कि बंगाल में इस बार के लोकसभा चुनाव में लाखों हिंदू मतदाताओं को वोट करने से रोक दिया गया था जिसके कारण उसकी करारी हार हुई। हाल ही में हुए रायगंज के उपचुनाव में भी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एक धर्म विशेष के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर भाजपा को हराने की साजिश रची गई। पार्टी ऐसे मतदाताओं का नाम और पता जानने की कोशिश कर रही है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करने दिया गया। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक वेबसाइट लॉन्च करते हुए लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को मतदान करने से रोक दिया गया था, वे इस पर अपना नाम-पता दर्ज कराएं।

10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, भाजपा और सपा में नूरा कुश्ती

■ केशव और अखिलेश ने एक-दूसरे पर किया हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा और सपा में नूरा कुश्ती तेज हो गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक-दूसरे पर हमला किया। प्रदेश की दस विधानसभा सीटों, कटेहरी (अंबेडकरनगर), करहल (मैनपुरी), मिल्कीपुर (अयोध्या), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), गाजियाबाद, मझवां (मिर्जापुर), सीसामऊ (कानपुर नगर), खैर (अलीगढ़), फूलपुर (प्रयागराज) और कुंदरकी (मुरादाबाद) पर उपचुनाव होने हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता 10 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। हाल के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की सीटों में भारी गिरावट के बाद राज्य में पहला चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ आवास पर सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी।

2022 के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 33 सीटें जीतीं। मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी की 37 सीट पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, सूबे में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है।

तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वह अपने दल के अंदर कर रही है इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचनेवाला भाजपा में कोई नहीं है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यादव के बयान पर पलटवार करते हुए 'एक्स' पर कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी,भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है,सपा का पीडीए धोखा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहरायेगी। फिर एकबार डबल इंजन सरकार।

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी को 'आगामी विधानसभा उपचुनावों में लोकसभा चुनावों से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे।' अखिलेश यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगामी उपचुनावों में हमें लोकसभा से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं।

हाल के लोकसभा चुनावों में सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की, जो 2019 की तुलना में 32 सीट अधिक हैं। दूसरी ओर भाजपा सिर्फ 33 सीट पर सिमटकर रह गई, जो पिछले चुनाव से 29 सीट कम है। उप्र में कथित 'भाजपा में अंदरूनी कलह' की ओर इशारा करते हुए यादव ने कहा, सत्ता की लड़ाई में जनता का नुक्सान हो रहा है।

यादव ने जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर का भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। यादव ने कहा, संविधान बचाने के हमारे हालिया आह्वान में, वह (विजय बहादुर) और उनके दोस्त पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर हमारी मदद कर रहे हैं।

अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर अग्निवीर के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र में 3 साल का छूट दिया जाएगा। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु संबंधी छूट 5 साल की होगी। सरकार अग्निवीरों को सिविल पदों पर सीधी भर्ती के लिए ग्रुप सी में 5 फीसदी आरक्षण और ग्रुप बी में 1 फीसदी आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि यदि अग्नि वीरों को किसी भी औद्योगिक इकाई की ओर से 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार देगी। उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। हरियाणा सरकार ने अपनी घोषणा में कहा है कि पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10 फीसदी आरक्षण के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन दिया जाएगा।

निजी उद्योगों में कन्नड़भाषी लोगों के लिए आरक्षण पर घिरे सीएम सिद्धारमैया

बेंगलूरू। कर्नाटक में कन्नड़ों को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए आरक्षण देने वाले विधेयक पर विवाद गहराता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल, उन्होंने पहले एक ट्वीट कर निजी उद्योगों में 'सी और डी' श्रेणी के 100 प्रतिशत पदों को कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों के लिए आरक्षित करने की बात कही। इस पर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे डिलीट कर नया ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को उनकी ही धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है।

दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक दिन पहले ही कहा था कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। इस विधेयक का उद्योगपतियों से लेकर विपक्ष तक ने विरोध किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे पहले कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया।

कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग

■ केटीआर ने साधा राहुल गांधी पर निशाना

हैदराबाद। तेलंगाना में जबरदस्त तरीके से सियासत जारी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के नेता लगातार पाला पदल रहे हैं। इन सब के बीच पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सभी 10 बीआरएस विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।

रामाराव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून के तहत दलबदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। बीआरएस नेता ने कहा कि चूंकि पार्टी ने पहले ही डी नागेंद्र को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर कर दी है, इसलिए उन्होंने शेष नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। बीआरएस प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष से उनकी अयोग्यता याचिका पर तुरंत निर्णय लेने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि स्पीकर दलबदलू विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेंगे। अगर वह निर्णय लेने में विफल रहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

बीआरएस नेताओं ने स्पीकर के ध्यान में लाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, स्पीकर को तीन महीने के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेना होगा। स्पीकर को यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मणिपुर में एक कांग्रेस विधायक को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विपक्षी दल के नेताओं ने स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फैसला लेने की मांग की। स्पीकर से कहा गया कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहे तो इससे पद की बदनामी होगी।

केटीआर, जिन्हें रामाराव के नाम से जाना जाता है, ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में अपने हाथों में संविधान लेकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी रक्षा करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उसी संविधान को तेलंगाना में उछाल रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य राज्यों में दलबदल को लेकर हंगामा मचा रहे थे, लेकिन तेलंगाना में दलबदल को बढ़ावा दे रहे थे। केटीआर ने स्पीकर के ध्यान में यह भी लाया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि अन्य दलों में शामिल होने वाले विधायकों को स्वत: अयोग्य घोषित करने के लिए कानून लाया जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में लेंगे हिस्सा

नईदिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने इस महीने के अंत 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों की सूची जारी कर दी है। पेरिस खेलों में भारत के 117 एथलीट हिस्सा लेंगे, जबकि 140 सहायक स्टाफ भी ओलंपिक के लिए जाएंगे। हालांकि, गोला फेंक एथलीट आभा खुटाआ का नाम इसमें शामिल नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्चे पर मंजूरी मिली है।

ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। विश्व रैंकिंग के जरिए कोटा हासिल करने वाली आभा खटुआ का नाम हटाने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले विश्व एथलेटिक्स की ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा। 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे जिसमे 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। इनके अलावा निशानेबाजी में 21 और हॉकी के 19 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में आठ खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि बैडमिंटन में सात खिलाड़ी होंगे जिसमे दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू शामिल हैं।

इनके अलावा कुश्ती के छह, तीरंदाजी के छह और मुक्केबाजी के छह खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। वहीं, गोल्फ से चार, टेनिस के तीन, तैराकी से दो, सेलिंग के दो और घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन से एक-एक खिलाड़ी इन खेलों में जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 119 सदस्यों का दल भेजा था और टीम ने एक स्वर्ण सहित सात पदक जीते थे जो ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

टाटा पावर 2024-25 में 20000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

नईदिल्ली। टाटा पावर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कंपनी की 105वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को बताया कि पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को गति देने के लिए होगा। बाकी राशि पारेषण और वितरण कारोबार पर खर्च की जाएगी। चंद्रशेखरन, जो टाटा संस के चेयरमैन भी हैं, ने कहा, ''टाटा पावर ने 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है। यह 2023-24 में निवेश की गई 12,000 करोड़ रुपये की राशि से काफी अधिक है।''उन्होंने कहा कि टाटा पावर अन्य राज्यों में नए वितरण विस्तार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी सरकार से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर में भागीदारी की संभावना भी तलाशेगी।

एडीबी ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% पर रखा बरकरार

नईदिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए 7 प्रतिशत पर स्थिर रखा। बैंक ने यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि और आवास निर्माण में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया। एडीबी ने कहा, केंद्र सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन, मौसम में बदलाव और भू-राजनीतिक झटकों से उत्पन्न जोखिमों को भी ध्यान में रखना होगा। एडीबी के जुलाई आउटलुक में कहा गया है कि सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी के साथ भारत का कृषि क्षेत्र फिर से मजबूत हो सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी खर्च से निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है।

प्रैट एंड व्हिटनी ने बेंगलुरु में खोला नया ग्राहक सेवा केंद्र

नईदिल्ली। अमेरिकी एयरोस्पेस प्रमुख प्रैट एंड व्हिटनी ने बेंगलुरु में एक नए ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसएस) की स्थापना की बुधवार को घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह नई सुविधा प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा के वैश्विक स्तर पर सेवारत 68,000 इंजनों के लिए ग्राहक सेवा और परिचालन सहायता को बढ़ावा देगी। इसमें कहा गया, इस सुविधा में 150 से अधिक एयरोस्पेस विशेषज्ञ तथा इंजीनियर कार्यरत होंगे, जो वैश्विक ग्राहक सेवा परिवेश को समर्थन प्रदान करेंगे। प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा के उपाध्यक्ष (ग्राहक कार्यक्रम) निवाइन कलब ने कहा, '' नए ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, हम भारत में अपने मौजूदा निवेश का लाभ उठा रहे हैं और अपने उत्पाद तथा सेवा की विश्वसनीयता तथा ग्राहक अनुभव सेवा स्तर को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहे हैं।''

सुजुकी ने अगले 10 वर्षों की प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार की

नईदिल्ली। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन भारत सहित विभिन्न बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अपने मॉडलों के लिए हल्के ढांचे और छोटी बैटरियों के इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। जापानी वाहन विनिर्माता ने अगले 10 वर्षों के लिए कंपनी की प्रौद्योगिकी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कॉम्पैक्ट तथा हल्के वाहन न केवल उपयोग के दौरान सीओ2 उत्सर्जन को कम करते हैं, बल्कि उत्पादन में भी संसाधनों के इस्तेमाल तथा सीओ2 उत्सर्जन को कम करते हैं। इस प्रकार ये संसाधन संरक्षण और सीओ2 कम करने में योगदान देते हैं। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया में करीब 58 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली इस कंपनी ने कहा कि वह हल्के वजन तथा सुरक्षा के लिए 'हार्टेक्ट' को और विकसित करेगी।

भारतीय परम्पराओं के अनुपालन से देश बढ़ रहा आगे

प्रह्लाद सबनानी

भारत जो किसी वक्त में सोने की चिड़िया रहा है जिसका किसी वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस भारत के गुलाम होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था को मुगलों ने एवं अंग्रेजों ने तहस-नहस किया है। भारत का सनातन चिंतन जितना अधिक शक्तिशाली था गुलामी के उस दौर में उस पर किए गए आक्रमण उसे कमजोर बनाने में कामयाब रहे। परंतु, अब समय आ गया है कि भारत के प्राचीन आर्थिक चिंतन को गंभीरता के साथ देखते हुए वर्तमान आर्थिक विकास की दृष्टि को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए तभी जाकर आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के वैभवकाल को पुन: प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत में प्राचीन ऋषियों और मनीषियों की परंपरा एक गृहस्थ परंपरा रही है और उस गृहस्थ परंपरा में आध्यात्म के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन भी जुड़ा रहा है। अपने राज्य के ऋषियों के जीवन यापन की चिंता जहां राजा की प्राथमिकता में रहता था वहीं राजा को राज्य चलाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने का सांस्कृतिक कार्य उन ऋषि-मुनियों द्वारा किया जाता था। इसलिए उन मनीषियों का चिंतन आर्थिक दिशा में भी सदैव बना रहता था। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध कैसे बनाएं इसके बारे में ऋषि-मुनियों के साथ बैठकर ही राज दरबार में चिंतन होता था और राज्य आर्थिक रूप से सशक्त बन जाते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।

प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों एवं धार्मिक पर्यटन का भारत के आर्थिक विकास

पर पूर्ण प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत में धार्मिक आयोजनों से अर्थव्यवस्था को बल मिलता रहा है इसलिए उस कालखंड में धार्मिक आयोजन निरंतर होते रहे हैं। भारत की ऋषि परंपरा ने जन सामान्य को उन सबके साथ जोड़ कर रखा था। त्यौहारों की निरंतरता और उन्हें मनाए जाने का उत्साह भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था को गति देता रहा है। आज के वक्त में भी धार्मिक पर्यटन के चलते भारतीय पर्यटन उद्योग में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा भी पिछले 10 वर्षों में भारत में विभिन्न तीर्थस्थलों को विकसित किया जा रहा है। अभी तक जो तीर्थस्थल विकसित हो चुके हैं,वहां का पर्यटन एकदम से कई गुना बढ़ गया है। वहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ गई है। वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। वहां संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए इस दिशा में सरकार अब आगे और कार्य करने जा रही है तथा कई नवीन धार्मिक कारीडोर बनाने जा रही है,क्योंकि इससे रोजगार के लाखों नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत की कुटुंब व्यवस्था अपने आप में एक अनूठी कुटुंब व्यवस्था है। भारत के संयुक्त परिवार विश्व के लिए आश्चर्य का विषय रहे हैं। इन दिनों संयुक्त परिवार विघटित अवश्य होते जा रहे हैं,लेकिन बावजूद उसके आपातकाल में एक दूसरे के लिए सबके एकत्र होने की जो जिजीविषा उन सबके भीतर है वह भारत में कुटुंब व्यवस्था का अनूठा स्वरूप है, तथा यह स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। एक परिवार में दो हाथ कमाने जाते हों और वहीं दस हाथ कमाने जाते हों, दोनों बातों का फर्क होता है। इसलिए कुटुंब व्यवस्था में एक दूसरे के लिए आपस में खड़े होने का जो व्यवहार होता है,वह व्यवहार आर्थिक चिंतन के साथ भी जुड़ कर परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है।

भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण को पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है। देश में नदियां शुद्ध रहती थी वृक्ष घने जंगलों के रूप में रहते थे और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहता था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को, वृक्षों को, धरती को पूजा जाता है। पूरे पर्यावरण से परिवार का जुड़ाव धार्मिक रूप से रहता है। बहुत सारे व्रत और त्यौहार पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए सनातन काल से भारत में पर्यावरण की चिंता रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मंडाविया से रोजगार सृजन श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं पर की चर्चा

श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार से की सहायता का आग्रह

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से उनके आवास पर सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने डॉ. मंडाविया से छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहायता का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में श्रम, रोजगार और खेल के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई

महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इनमें न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग की।

मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया को राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने डॉ. मंडाविया से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को और अधिक समर्थन दे, ताकि राज्य के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। डॉ. मंडाविया ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों की सराहना की और राज्य में विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हरसंभव सहयोग देने को तैयार है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार से मंत्री राजवाड़े ने की मुलाकात

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार खटीक से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री डॉ. खटीक को बस्तर के आदिवासियों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध ढोकरा कलाकृति भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. खटीक ने शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आने के साथ दिव्यांगजनों की भलाई के लिए कार्य करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

राज्य के हितों को दरकिनार कर साय सरकार ने राजस्थान को कोल उत्खनन की अनुमति दे दिया

दलीय प्रतिबद्धता में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी किया

रायपुर। राज्य के हितों को दरकिनार कर साय सरकार ने राजस्थान को कोल उत्खनन की अनुमति दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग उत्खनन के लिये दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस आशय की जानकारी सोशल मीडिया में दिया है। दलीय प्रतिबद्धता में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के हितों तथा राज्य के पर्यावरण को अनदेखी किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राज्य के हितों को देखते हुये यहां पर उत्खनन की अनुमति देने से मना कर दिया था जबकि उस समय राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने राज्य के हितों से समझौता नहीं किया था। इस खदान को रद्द करने कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भी भेजा था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में राज्य के कोल उत्खनन की बंदरबांट शुरू हो गयी है। भाजपा सरकार अडानी के हितों को सवंर्धित करने के लिये राज्य के जल, जंगल, जमीन खनिज संपदा को अडानी को सौपना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके है। यहां पर कटाई के लिये आदेश और पर्यावरण स्वीकृत केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था तब कांग्रेस सरकार ने इस स्वीकृति को राज्य के स्तर पर निरस्त कर दिया था तथा केंद्र में भी इसे निरस्त करने के लिये पत्र लिखा था। 31.10.2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माईंस कोल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने तथा वन कटाई के प्रस्ताव को निरस्त करने को कहा था। विधानसभा से भी कांग्रेस सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोल खदानों को निरस्त किया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्तावित प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। इस दौरान मोदी सरकार के कोयला मंत्री ने रायपुर आकर यह भी कहा कि जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां पेसा कानून के प्रावधान लागू नहीं होते किसी के आपत्ति या सहमति से कोल खनन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बाबू भैया की कलम से ✍

गौसंरक्षण: खुद बदलोगे सब बदलेगा

भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज है। तो पुराने में भी अपना किया हुआ, कुछ नया दिखना चाहिए। कृषक पशु परिरक्षण(संशोधन)अधिनियम,छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014,पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960,और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम 2017 को छत्तीसगढ़ की वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार संशोधन के माध्यम से नए प्रावधान के साथ फिर सामने लाई है। गृहमंत्री विजय शर्मा की सूचना के अनुसार सारे पुराने प्रावधानों के साथ अब यह जुड़ गया है कि बगैर लायसेंस कोई भी, किन्ही भी परिस्थिति में ,चाहे पैदल ले जा रहा हो ,चाहे किसी भी वाहन के माध्यम से ले जा रहा हो,चाहे एक हो या कितनी भी संख्या हो एक बार में 20 पशुधन ले जा रहा हो, तो उसे सक्षम अधिकारी से लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वाहन के सामने एक फ्लैक्स भी प्रदर्शित करना होगा कि वह किस प्रयोजन हेतु कहाँ उपरोक्त पशुधन ले जा रहा है। अन्यथा उसे अवैध मान कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही सात साल की जेल तथा 50हजार का जुर्माना की हो सकती है। हालांकि इतनी ही कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान पुराने कानून में भी है। इसे नए बयान के द्वारा पुन: दोहराया गया है। इन नियमों के बाद भी यदि कोई प्रकरण अवैध परिवहन का पकड़ा जाता है तो जिस जिस थाना क्षेत्र व जिले से वह गुजरा हो,अपराधी निकला हो उन थानों के अधिकारियों व कलेक्टर के सर्विस बुक में नेगेटिव टिप्पणी अंकित किये जाने की बात भी कही गई है।यह नया प्रावधान जोड़ने की बात कही गई है। शायद सरकार आये दिन हो रही ,पशु परिवहन की सूचनाओं व घट रही घटनाओं से परेशानी महसूस कर रही है।माब लीन्चिग जैसी घटनाएं भी घट चुकी हैं। जिस पर एक समुदाय के लोगों पर हमला होने पर सरकार की भी आलोचना हो रही है। सरकार की मंशा है कि ऐसे प्रकरण व घटनाओं पर रोक लगे। जो वास्तव में कुछ अवैध कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके कार्यवाही भी हो। ऐसे लोग भविष्य के लिए निगरानी में रखे जा सकें। एक कड़ा प्रावधान यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर बगैर लायसेंस परिवहन करते पकड़ा जाता है। उस पर गैर जमानती कार्यवाही होगी। वाहन राजसात करने के साथ वाहन मालिक पर भी कड़ी प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके साथ ही इस तरह के कार्यों से जो भी पैसा कमाई की जा रही है अथवा सम्पति बनाई गई है,उसे कुर्क किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पशुधन की रक्षा के लिए इस तरह कड़ा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले ही 20 राज्यों में गौहत्या व गौमांस बिक्री पर रोक के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10 हजार जुर्माना व 5 साल की सजा है। मप्र में तस्करी पर 5 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना,गुजरात में सबसे कड़ा कानून मौजूद है। गौहत्या पर वहां उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। हरियाणा में 1 लाख जुर्माना व 10 साल तक की सजा है।उत्तर प्रदेश में 10 साल जेल व 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। पहले सिर्फ गौ हत्या पर सजा का प्रावधान था लेकिन अब गौ तस्करी पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। गौ हत्या -तस्करी अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। प्रयास बुरा नहीं है। गौ को हम माता की श्रेणी में मानते ,पूजते हैं। हमारे सनातन धर्म में मां का क्या स्थान होता है ,हम वही स्थान गौधन को देते हैं। गौधन से उत्पन्न सभी उत्पादन मानव स्वास्थ्य व शरीर के लिए अमृत माने जाते हैं। हम गौ के सारे शरीर में ब्रह्मांड के दर्शन करते हैं। गाय के दूध से लेकर गोबर तक हमारे दैनिन्दिनी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव सेहत,संस्कृति की सेहत,धार्मिक भावनाएं गौमाता द्वारा संरक्षित हैं। उसकी रक्षा करना ना हमारा सिर्फ कर्तव्य है बल्कि हमारा धर्म भी है। गौरक्षा के लिए जो भी किया जा सके करना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि कैसे किया जा सकता है। क्या सिर्फ सरकारी प्रावधान कर देने मात्र से या चाह लेने से यह सम्भव हो जायेगा। आपने अधिनियम बना लिए कह दिया नोडल अधिकारी बनाएंगें। अब तक अधिकार जिला के कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को है। कचहरी के चक्कर का अनुभव हिंदुस्तान की जनता को कडुआ रहा है। वहां हर आमआदमी की पहुंच पकड़ नहीं हो पाती। एक किसान को अगर अपने बीमार पशु को इधर उधर ले जाना हो। या अपने पशुधन को बेचना हो। परिवहन की जरूरत होगी। बड़े अधिकारियों तक पहुंचना किसान के लिए परेशानी का सबब हमेशा रहा है। क्या उसके लिए वकीलों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या गांव स्तर के किसी संस्थाओं को अधिकार दिया जाएगा। कहीं यह भ्रष्टाचार का रास्ता तो नहीं खोल देगा। अभी अनेक राज्यों में राज्य के बाहर पशु परिवहन अनुमति के लिए कलेक्टर के कार्यालय में 5 हजार जमा करवाने पड़ते हैं। अनुमति लेने में पसीने छूट जाते हैं। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसका फायदा सिस्टम नहीं उठाएगा ,इसकी गारंटी लेनी होगी। अंत में यह भी कि गौ रक्षा की बात करने वाले कितने लोग अपने दैनिन्दिनी जीवन में गौसेवा करते हैं। कितने लोग उन्हें प्लास्टिक पन्नी खाने से रोकने उनकी खाने की व्यवस्था करते हैं। रोकना उन्हें भी चाहिये जो दूध निकालने के बाद गौमाता को लावारिस सड़क पर वाहनों की चपेट में आकर अंतिम सांस लेने छोड़ कर चैन की नींद सोते हैं। अपने अपने दिल पर हाथ रख कर विचारना होगा, गौमाता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आपको यह भी ध्यान रहे कि तभी आप गऊमाता के बारे में बात करने के अधिकारी हो सकेंगें। काम बहुत अच्छा है सबको मिलकर गौमाता की रक्षा का काम करना चाहिए। सिर्फ बंदिशों की घोषणाओं से कुछ नहीं बदलेगा,पहले अपने आपको बदलना होगा।

हाईकोर्ट ने जलाकर मारने मामले में दो लोगों की सजा को रखा बरकरार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान माना कि मौत से पहले दिए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं, इसके लिए शर्त है कि मरीज को डॉक्टर ने फिटनेस प्रमाण पत्र दिए हो कि वह बयान देने के लिए फिट है। साथ ही मरीज का बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज होगा। इस टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने 18 वर्षीय लड़की को जलाकर मार डालने के लिए दो लोगों की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि 16 अगस्त

2020 की रात बलौदा बाजार जिले के सुहेला में गंगा यादव की जलने से मौत हो गई थी। मामले में कहा गया कि यादव समाज भवन में हुए विवाद के बाद अजय वर्मा ने गंगा को आग लगा दी थी। वर्मा और सह-आरोपी अमनचंद रौतिया को बलौदा बाजार-भाटापारा ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अभियोजन पक्ष की दलीलों का केंद्र गंगा का मृत्यु पूर्व बयान था, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट अंजलि शर्मा ने डॉ. दीपिका सिन्हा द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के बाद दर्ज किया था।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

गौ तस्करी रोकने में भाजपा सरकार नाकाम

रायपुर। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर गौ हत्यारी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी रायपुर में गौसेवकों गौ मांस का पकड़ा जाना पूरे प्रशासनिक फेलियर और सरकार के निकम्मेपन का प्रमाण है। सरकार अपनी असफलता छुपाने सजा बढ़ाने को प्रचारित कर रही है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नही की जा रही है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है गांव तस्करी की घटनाएं बढ़ गई है। फरवरी 2024 में कुम्हारी, सरोना के पास 120 गायों से भरे कंटेनर गौसेवकों ने पकड़ा था, जिसमें 13 गायों की मौत हो चुकी थी। हाईवे में फर्जी नंबर प्लेट लगा कंटेनर सरपट दौड़े, यह बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं। आरंग में हाल ही में महानदी पुल पर गौ तस्करी के आरोप में लिंचिंग में तीन लोगों की हत्या हुई और अब राजधानी रायपुर के गुढियारी में गौ मांस पकड़े जाने की घटना, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता, अकर्मण्यता, गौ तस्करों और गौ हत्यारे को मिलने वाले संरक्षण का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गाय और गोबर के नाम पर केवल राजनीति करती है।

कांग्रेस सरकार के कार्यो का राष्ट्रीय पुरस्कार भाजपा सरकार ले रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए जनता की भलाई के कार्यो का राष्ट्रीय पुरस्कार भाजपा की सरकार ले रही है। बीते 6 महीने में भाजपा सरकार ने शहर के निवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने उनके आजीविका को बेहतर बनाने उनके आर्थिक मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया है जिसका उसे पुरस्कार मिलेगा। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं वह कांग्रेस के सरकार के दौरान हुए कामों का परिणाम है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार भाजपा को चिढ़ा रही है जो भाजपा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार पर शहरी गरीब परिवार के आजीविका सुधारने के लिए कोई काम नहीं करने झूठा आरोप लगाते थे जब भाजपा सरकार के मंत्री यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे तब उन्हें अपने झूठे आरोपो पर अफसोस होगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने व्यक्ति विकास की नीति अपनाकर हर वर्ग की चिंता की है हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाया है। जहां मोदी सरकार के गलत नीतियो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी आर्थिक मंदी रही धंधा, व्यवसाय चौपट था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक मंदी नहीं था.

प्रदेश का राजस्व विभाग ठप्प पड़ा है - कांग्रेस

रायपुर। कर्मचारियों के हड़ताल के कारण राजस्व विभाग ठप्प पड़ा हुआ है। आम आदमी पटवारी से लेकर तहसील ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की अनुभवहीनता और अदूरदर्शिता का खामियाजा प्रदेश की जनता भोगने मजबूर है। किसानी का समय है, खरीफ की बुवाई हो चुकी है, रोपा बियासी की तैयारी है। राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल के चलते नामांतरण और बटवारा, हक्त्याग, त्रुटि सुधार, ऋण पुस्तिका जैसे काम के लिए आम जनता को तहसील कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार का पूरा फोकस वसूली गैंग चलाने में है, भू माफियाओं को सरकारी संरक्षण है, खसरा लॉक करके मोटा रकम वसूला जा रहा है। आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों और पालकों की परेशानी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारी की ज्यादातर मांगे, आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर है। संशोधन और त्रुटि सुधार के अधिकार के लिए है।

बलौदाबाजार हिंसा मामला: आज बलौदाबाजार आएंगे न्यायिक आयोग के अध्यक्ष

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम काटे जाने व बलौदाबाजार हिंसा आगजनी की न्यायिक जांच गति पकड़ रही है. प्रकरण की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सीबी बाजपेयी 18 जुलाई को सुबह नौ बजे बलौदाबाजार पहुंचेंगे, जहां से गिरौदपुरी व महकोनी स्थित अमर गुफा जाकर घटना की जांच करेंगे. बता दे कि अमर गुफा स्थित जैतखाम काटे जाने और उसके बाद पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट सतनामी समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी जिसके बाद राज्य शासन ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था. वहीं घटना से आक्रोशित सतनामी समाज ने बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में प्रदर्शन किया था, जिसमें पूरे प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से भी लोग पहुंचे थे. प्रदर्शन के बाद कलेक्टर व एसपी कार्यालय में आगजनी हिंसा तोड़फोड़ की घटना हुई थी.

जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले: कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य और केन्द्र प्रवर्तित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप कहा कि शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले के विषम परिस्थिति के बावजूद विभागीय समन्वय के साथ विकास कार्यो में बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिकारियों का उत्साहवर्धन भी किया। बैठक में बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित थे।

हर श्रमिक तक पहुंच रही योजना: देवांगन

विष्णु सरकार में श्रमिकों का भरोसा फिर लौटा

रायपुर। श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज कोरबा जिले के बुधवारी बजार में शहीद वीर नारायणसिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत निर्माण, संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिकों के लिए 05 रूपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था हेतु दाल-भात केंद्र का शुभारंभ किया। यह जिले का दूसरा दाल भात केंद्र है। इस दौरान उन्होंने अतिथियों के साथ स्वयं भी श्रमिकों के बीच जाकर भोजन किया और श्रमिकों से अपील किया कि वे इस दाल-भात केंद्र में आकर भोजन अवश्य करें। श्रम मंत्री ने इस अवसर पर विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि श्रम विभाग से जुड़े कुल तीन मंडल अंतर्गत 72 योजनाएं संचालित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी योजनाओं में हितग्राहियों को सामग्री प्रदान करने की बजाय सीधे उनके खाते में राशि देने की पहल किया है। इससे हितग्राही को सीधा लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि श्रम विभाग की योजना श्रमिकों

के लिए है। छत्तीसगढ़ का कोई भी श्रमिक योजनाओं से वंचित न रहे, उन्हें लाभ जरूर मिले। श्रम मंत्री होने के नाते उनकी भी कोशिश है कि कोरबा जिले के सभी श्रमिक योजनाओं का लाभ उठाएं।

बुधवारी में दाल-भात केंद्र का शुभारंभ करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तत्काल सहमति दी और आज उनके प्रयास से गरीब मजदूरों को किफायती दर में प्रदेश के 10 जिलों के 22 स्थानों में दाल-भात केंद्र संचालित हो रहा है। कोरबा जिले में तीन स्थानों पर दाल-भात केंद्र का संचालन होगा। जिसमें से बालकों के बाद आज दूसरा केंद्र प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को साल के 12 हजार रूपए का लाभ मिलने, किसानों को 3100 रूपए समर्थन मूल्य तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रूपए मानक बोरा सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए आईएएस, आईपीएस सहित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देने पहल की गई है।

गौ-तस्करी के शक में हुई मॉब लिंचिंग मामले में पांच आरोपियों गिरफ्तार

रायपुर। आरंग के पास महानदी पुल पर 7 जून को गौ-तस्करी के शक में हुई कथित मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी प्रमुख एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया है। चालान पेश होने के बाद अब अदालत में मुकदमा शुरू हो जाएगा।

घटना का विवरण- तनय लूनिया युवकों के उस ग्रुप का लीडर था, जो गौवंश से भरे ट्रक का पीछा कर रहे थे।

यह पीछा रात में किया गया था और कुछ घंटे बाद पुल के नीचे सहारनपुर (यूपी) के दो युवकों चांद मियां और गुड्डू खान के शव मिले, जबकि तीसरा युवक सद्दाम गंभीर रूप से घायल पाया गया था। सद्दाम की भी एक हफ्ते बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि गौवंश से भरे ट्रक का पीछा किया गया था और पुल पर मारपीट भी हुई थी। जांच के मुताबिक, मारपीट और धमकी से डर कर संभवत: तीनों ने पुल से छलांग लगाई होगी, लेकिन तीनों पथरीली सतह पर गिरे। इसके बाद से माब लिंचिंग की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। माब लिंचिंग की आशंका को देखते हुए एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एसआईटी का गठन किया था। मौतों के मामले में दफा 308 का केस रजिस्टर किया गया था। एसआईटी ने लगभग 15 दिन तक सारे सबूतों की पड़ताल के बाद गिरफ्तारियां शुरू की थीं। एसआईटी प्रमुख एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि तफ्तीश जारी रहेगी और बाद में अन्य आरोपियों का पता चलेगा, तो उनकी भी गिरफ्तारी कर पूरक चालान पेश किया जा सकता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.